● वर्ष-5
● अंक-205
रायपुर, मंगलवार
14 अप्रैल 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8> बस्तर में स्वास्थ्य क्रांति की नई

महिला आरक्षण पर पीएम मोदी का बड़ा कदम, बोले-

इतिहास रचने को तैयार संसद

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतांत्रिक ढांचे में महिलाओं के लिए आरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी देश के लोकतंत्र को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि भारत की नारी शक्ति ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है और संसद के बजट सत्र का विशेष सत्र इसी महीने की 16 तारीख से आयोजित होने जा रहा है।

मोदी ने कहा कि हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास, जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत का संकल्प जो समतामूलक हो, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा न हो, बल्कि हमारी कार्य संस्कृति का, हमारी निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हो। राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 अप्रैल है। 2023 में नई संसद में हमने नारीशक्ति वंदन अधिनियम के रूप प्रथम कदम उठाया था। वह समय से लागू हो सके, महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूती दे, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है और उससे पहले आज नारीशक्ति वंदन का ये कार्यक्रम, इसके जरिए हमें देश की कोटि-कोटि माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है।

आप सभी देश के कोने-कोने से आई हैं। आपकी इस उपस्थिति के लिए, इस महत्वपूर्ण काम के लिए, आपने जो समय निकाला है, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही भारत की सभी महिलाओं को एक नए युग के आगमन की बधाई भी देता हूं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था। इस विमर्श को करीब 4 दशक बीत गए। इसमें सभी पार्टियों के और कितनी ही पीढ़ियों के प्रयास शामिल हैं। हर दल ने इस विचार को अपने-अपने ढंग से आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था। तब एक सुर में ये बात भी उठी थी कि इसे हर हाल में 2029 तक लागू हो जाना चाहिए। खासकर, हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने मुखर होकर इस बात पर जोर डाला था कि 2029 में ये लागू हो जाना चाहिए।

महिला आरक्षण से आधी आबादी को मिलेगा पूरा हक: मुख्यमंत्री साय

रायपुर। सीएम विष्णुदेव साय ने सोमवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नई दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रसारित 'नारी शक्ति वंदन सम्मेलन' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह देश की मातृशक्ति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक समावेशी एवं सशक्त बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। यह समय देश की आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार दिलाने और उन्हें विकास की मुख्यधारा में निर्णायक भूमिका देने का है।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 'पंचायत से पार्लियामेंट तक' नारी की भागीदारी सुनिश्चित करने का यह प्रयास नए भारत की झलक दिखाता है। निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सीधी भागीदारी ही विकसित भारत की सशक्त नींव है। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को संसद में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर होने वाली चर्चा इस ऐतिहासिक पहल को मूर्त रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की महातैयारी

जनगणना के लिए 1 मई से घर-घर पहुंचेगा प्रशासन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां निर्णायक चरण में पहुंच गई हैं। गृह विभाग की सीधी निगरानी में राज्य सरकार ने इस महाअभियान का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रायपुर के सिविल लाइन सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगवा और जनगणना कार्य निदेशक कार्तिकेय गोयल ने बताया कि राज्य में 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण और हाउसिंग सेंसस का पहला चरण चलेगा। पहली बार यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल मोड और सेल्फ एन्यूमरेशन के विकल्प के साथ होगी।

गृह विभाग की निगरानी में तेज हुई तैयारियां

गृह विभाग ने जनगणना 2027 को राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद मानते हुए इसकी कमान अपने हाथ में रखी है। राज्य स्तर से लेकर जिला और तहसील स्तर तक लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगवा स्वयं इस अभियान की

मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि कोई भी शहरी या ग्रामीण इलाका सर्वे से छूट न जाए। विभाग का जोर इस बात पर है कि आंकड़े पूरी तरह सटीक और भरोसेमंद हों, जिससे भविष्य की विकास योजनाओं के लिए मजबूत आधार तैयार हो सके।

पहले चरण में 1 मई से 30 मई 2026 तक प्रगणक (डेटा इकट्ठा करने वाला कार्यकर्ता) घर-घर जाकर मकानों और परिवारों की जानकारी जुटाएंगे। इस दौरान मकान की स्थिति, निर्माण का प्रकार, पानी-बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं, परिवार की संरचना और उपलब्ध परिसंपत्तियों से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी। गृह विभाग ने इस चरण को राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि यही डेटा आगे जनसंख्या गणना के दूसरे चरण की नींव बनेगा।

इस बार जनगणना की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजिटल स्वरूप है। नागरिक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं अपनी जानकारी भर सकेंगे। जानकारी दर्ज करने के बाद एक जनरेट होगी, जिसे घर आने वाले प्रगणक को दिखाना होगा। प्रगणक की पुष्टि के बाद ही रिकॉर्ड अंतिम रूप से सुरक्षित होगा। गृह विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से डेटा संग्रह की गति बढ़ेगी और त्रुटियों की संभावना कम होगी।

62 हजार कर्मी मैदान में

राज्य में इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए गृह विभाग ने लगभग 62,500 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। इसमें प्रमुख जनगणना अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी, चार्ज अधिकारी, मास्टर ट्रेनर्स, प्रगणक और पर्यवेक्षक शामिल हैं। यह पूरा अमला 33 जिलों, नगरीय निकायों और गांवों तक पहुंचकर सुनिश्चित करेगा कि हर घर की जानकारी समय पर दर्ज हो।

आशा भोसले का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

मुंबई। भारतीय संगीत जगत की महान गायिका आशा भोसले का सोमवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुंबई के शिवाजी पार्क श्मशान घाट में उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जहां महाराष्ट्र पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें सलामी दी।अंतिम संस्कार के दौरान माहौल बेहद भावुक रहा। बॉलीवुड के गायकों और संगीतकारों ने उनके अमर गीत 'अभी ना जाओ छोड़कर' गाकर उन्हें स्वरांजलि अर्पित की। यह गीत उनके सुनहरे संगीत सफर की याद दिलाता रहा, जिसने दशकों तक श्रोताओं के दिलों पर राज किया। इससे पहले सुबह उनके पार्थिव शरीर को लोअर परेल स्थित उनके निवास 'कासा ग्रांडे' में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मतदान का सवाल ही नहीं उठता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में उन लोगों को राहत नहीं दी, जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान काटे गए हैं और उनकी अपील अपीलीय न्यायाधिकरण (अपीलेट ट्रिब्यूनल) के सामने लंबित हैं।

कोर्ट ने कहा कि, वोटिंग का सवाल ही नहीं उठता और अगर उन्हें इजाजत दे दी गई है तो हमें उस पर भी रोक लगा देनी चाहिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया। हालांकि, बेंच ने इशारा किया कि वह उन लोगों को शामिल करने के लिए सप्लीमेंट्री रोल प्रकाशित करने की अनुमति देने की अर्जी पर विचार कर सकती है जिनकी अपील

विधानसभा चुनावों से पहले मंजूर हो गई हैं।

सुनवाई के दौरान, पश्चिम बंगाल में एसआईआर को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की तरफ से सीनियर वकील कल्याण बंद्योपाध्याय ने कहा कि, 6 अप्रैल को रघुनाथगंज चुनाव क्षेत्र में वोटर लिस्ट प्रकाशित की गई है।।सभी पर फैसला हो रहा है। बेंच ने बताया कि सूची में सिर्फ 1800 से ज्यादा वोटर हैं। बंद्योपाध्याय ने कहा कि यह पहला चरण है और यह एक केस उनकी जानकारी में आया है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस केस पर फैसला होना है, वह अभी भी लंबित है। जस्टिस बागची ने कहा कि जिन लोगों के दावों पर 9 अप्रैल तक फैसला हो गया था, जिस तारीख को रोल फ्रीज किए गए थे, वे 23 अप्रैल को वोट कर सकते हैं।

प्रमुख समाचार

उर्दू जहां बोली जाती है वहां जाओ, यहां बांग्ला चलेगी: योगी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने लोगों से राज्य में एक क्र्रबल इंजनक्र्वाली बीजेपी सरकार बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ही वास्तव में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करेगी. उन्होंने कहा कि जो कहते हैं कि बंगाल में उर्दू बोली जाएगी, उनसे कह दो- उर्दू जहां बोली जाती वहां जाएं, बंगाल में बांग्ला ही बोली जाएगी. दरअसल, योगी आदित्यनाथ का यह बयान कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के उस वायरल वीडियो के संबंध में था, जिसमें वह कहते सुने गए कि एक दिन बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी. हकीम का यह कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो है, जिसमें वे कह रहे हैं, क्र्रइंशाल्लाह, बंगाल में एक दिन ऐसा आएगा जब आधी आबादी उर्दू बोलेगी.क्र्र हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब और कहां रिकॉर्ड किया गया था।

चाय में मिलाएंगे नींद की दवाई और चुरा लेंगे वोट: ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कई बड़ी रैलियां कीं। आसनसोल, छतना, ओंदा और खंडाघोष में उन्होंने भाजपा के बाद एक बड़े आरोप लगाए। टीएमसी के उम्मीदवारों को डराने से लेकर बंगाल को तीन टुकड़ों में बांटने की साजिश तक, ममता ने कई बड़े दावे किए.पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ दिनों विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है. कुल 294 सीटें हैं और बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए. 2021 में भाजपा ने 77 सीटें जीती थीं। ममता की पार्टी टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। इस बार भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे करके पूरी ताकत लगाई है। इसी माहौल में ममता ने रैलियों में कई बड़े दावे किए। ममता ने कहा कि भाजपा अभी से टीएमसी के उम्मीदवारों को, यहां तक कि राज्य सरकार के मंत्रियों को भी फोन कर रही है. भाजपा उन्हें धमकी दे रही है कि अगर चुनाव के बाद उनके पास बहुमत कम पड़ा तो वो उनका साथ दें।

हम किसी की बी-टीम नहीं: ओवैसी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी हलचल के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को मुर्शिदाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर तीखा हमला बोला। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी किसी की बी-टीम नहीं है और वे स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के साथ चुनाव मैदान में उतरते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी का अतीत भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है और उन्होंने पुराने राजनीतिक घटनाक्रमों का हवाला देते हुए उनके रुख पर सवाल उठाए। अपने भाषण में ओवैसी ने कहा कि 2003 में भाजपा द्वारा समर्थन और उसके बाद हुए गुजरात दंगे 2002 का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि उस समय ममता बनर्जी की क्या भूमिका थी। उन्होंने इशरत जहां, बिलकिस बानो और जकिया जाफरी जैसे मामलों का हवाला देते हुए कहा कि क्या ये सभी उनके लिए मायने नहीं रखते ?यहां ओवैसी ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल मुसलमानों से नहीं, बल्कि उनके वोटों से प्रेम करते हैं।

तीन जुलाई से शुरू होगी बाबा अमरनाथ की यात्रा

नईदिल्ली। अमरनाथ यात्रा 2026 की घोषणा हो चुकी है. श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अनुसार, इस साल की वार्षिक तीर्थयात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होगी. इसका समापन 28 अगस्त 2026 को रक्षा बंधन के अवसर पर होगा. इस बार ये यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है. यात्रा के औपचारिक आरंभ से पहले, भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए प्रथम पूजा का आयोजन किया जाएगा. यह विशेष पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, यानी 29 जून 2026 को संपन्न होगी. इसी दिन से यात्रा के लिए आध्यात्मिक वातावरण तैयार हो जाता है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ के प्रबंधन के लिए अग्रिम पंजीकरण अनिवार्य है. इस साल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगी. भक्त ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अपना पंजीकरण करा सकते हैं. ऑफलाइन माध्यम देशभर में स्थित जम्मू-कश्मीर बैंक, पीएनबी , एसबीआई और यस बैंक की 554 शाखाओं पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।

पूरी पार्टी पवन खेड़ा के साथ खड़ी, हम डरने वाले नहीं: राहुल

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा पर कई पासपोर्ट रखने के आरोपों के बीच पवन खेड़ा का समर्थन करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने सरमा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताकर कांग्रेस के आरोपों की जांच की मांग की। राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को परेशान करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना संविधान के खिलाफ है। पारदर्शिता, सत्ता की जवाबदेही और कानून का शासन हमारे संवैधानिक मूल्यों का आधार हैं। कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के साथ खड़ी है। हम डरने वाले नहीं हैं। ये टिप्पणियां असम पुलिस द्वारा तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद आईं, जिसमें कांग्रेस नेता खेड़ा को 10 अप्रैल से एक सप्ताह के लिए कुछ शर्तों के साथ पारगमन जमानत मिली थी।

हैदराबाद में आयोजित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना की वार्षिक बैठक में मिला सम्मान

कृषि विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ सोयाबीन अनुसंधान केंद्र का राष्ट्रीय पुरस्कार

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (सोयाबीन) को राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2023-2025 की मूल्यांकन अवधि के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मान के लिए कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री राम विचार नेताम ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। यह सम्मान राष्ट्रीय अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (सोयाबीन) नेटवर्क के अंतर्गत प्रदान किया गया। यह पुरस्कार रायपुर केंद्र की बहुआयामी उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया गया जिसमें अनुसंधान परीक्षण, वैज्ञानिक प्रकाशन, प्रजनन नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास, किसान संपर्क कार्यक्रम और बीज उत्पादन शामिल हैं। यह पुरस्कार अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (सोयाबीन) विश्वविद्यालय टीम के सदस्यों डॉ. सुनील कुमार नाग (प्रधान वैज्ञानिक), डॉ. रामा मोहन सावु (वरिष्ठ वैज्ञानिक) एवं डॉ. ऐश्वर्या टंडन (सह-प्राध्यापक) द्वारा प्राप्त किया गया। यह सम्मान डॉ. प्रताप सिंह, माननीय कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर; डॉ. एस.के. राव, पूर्व कुलपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर; डॉ. के.एच. सिंह, निदेशक, आईसीएआर-राष्ट्रीय

सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर तथा डॉ. आर.के. माथुर, निदेशक, आईसीएआर-भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद द्वारा 09 अप्रैल 2026 को हैदराबाद स्थित प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र नगर में आयोजित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (सोयाबीन) की 56वीं वार्षिक समूह बैठक में प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने पुरस्कृत अनुसंधान दल के टीम लीडर एवं सदस्यों को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं हैं। यह पुरस्कार व्यापक मूल्यांकन प्रणाली और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर केंद्र ने असाधारण उपलब्धियाँ प्रदर्शित कीं।

केंद्र ने लगातार तीन वर्षों तक पादप प्रजनन, सस्य विज्ञान, पादप रोग विज्ञान एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में सभी आवंटित परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किए और उनकी स्वीकृति प्राप्त की। सोयाबीन अनुसंधान से संबंधित उच्च-गुणवत्ता वाले नास रेटेड शोध पत्र, सम्मेलन पत्र, बुलेटिन तथा एम.एससी. एवं पीएच.डी. छात्रों के मार्गदर्शन के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। केंद्र ने सुदृढ़ जर्मप्लाज्म प्रबंधन (प्रति वर्ष 1000 से अधिक अभिग्रहण), व्यापक संकरण कार्यक्रम तथा आएससी 11-42, आएससी 11-72 और आएससी 12-32 जैसी उत्कृष्ट किस्मों के विकास में प्रगति की। प्रमुख उपलब्धियों में पूर्वी क्षेत्र के लिए तीन उन्नत सोयाबीन किस्मों का विकास, छह उत्पादन एवं संरक्षण तकनीकों का विकास तथा तीन जर्मप्लाज्म लाइनों का पंजीकरण शामिल है। केंद्र ने प्रति वर्ष 100 फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन, कांकेर जिले में जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत किसानों को लाभान्वित करने तथा नियमित किसान प्रशिक्षण एवं खेत प्रदर्शन के माध्यम से उत्कृष्ट विस्तार कार्य किया। प्रजनक बीज उत्पादन में लगभग 90 लक्ष्य प्राप्ति के साथ-साथ न्यूक्लियस बीज उत्पादन में भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई।

केंद्र ने बड़े जर्मप्लाज्म संग्रह के मूल्यांकन, उच्च उपज एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों के विकास, समेकित पोषक तत्व एवं खरपतवार प्रबंधन सहित टिकाऊ कृषि पद्धतियों में नवाचार तथा जलवायु-अनुकूल एवं किसान हितैषी तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने सशक्त विस्तार तंत्र के माध्यम से अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना एवं सोयाबीन केंद्र ने उच्च उपज वाली किस्मों एवं उन्नत फसल प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देकर, लक्षित हस्तक्षेपों के जरिए जनजातीय किसानों को सहयोग प्रदान कर तथा टिकाऊ एवं यंत्रीकृत कृषि तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ाकर सोयाबीन उत्पादकता और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

तेलंगाना कैडर की हार्डकोर नक्सली एसीएम रुपी ढेर

■ एसीएम कमांडर रूपी तेलंगाना की अंतिम तेलुगू कैडर थी, जिसने अबतक सरेंडर नहीं किया था. वो बस्तर इलाके में सक्रिय थी.

कांकेर मुठभेड़ में मिली सफलता, डेडबॉडी बरामद

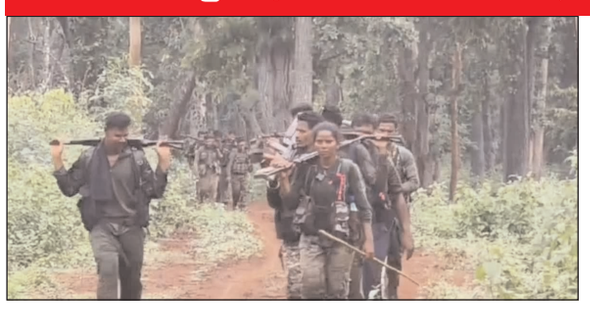

कांकेर। छोटे बेठिया और परतापुर के बॉर्डर इलाके में आज सुबह माओवादियों और जवानों के बीच नक्सल मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में जवानों ने एक महिला माओवादी को मार गिराया। मारी गई महिला माओवादी की पहचान ,ष्टरू कमांडर रूपी के रूप में की गई है।

रूपी तेलंगाना की अंतिम तेलगु कैडर थी जिसने अबतक सरेंडर नहीं किया था। अपने साथियों के सरेंडर करने के बावजूद वो बस्तर इलाके में सक्रिय थी। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि जिला कांकेर के छोटेबेठियाङ्कपरतापुर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके के माचपल्ली, आरामझोरा, हिड्डूर क्षेत्र के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस बल को सर्च ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया था। सर्च अभियान के दौरान पुलिस बल और माओवादियों के बीच माचपल्ली इलाके में मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर खत्म होने के बाद इलाके में सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया। सर्चिंग के दौरान सुरक्षाबलों को 1 महिला माओवादी कैडर का शव मिला। मुठभेड़ में बरामद माओवादी कैडर के शव की पहचान महिला माओवादी कमांडर एसीएम रूपी के रूप में की गई। एसीएम रूपी, डीकेएसजेडसी सदस्य विजय रेड्डी की पत्नी थी। जिसकी वर्ष 2025 में जिला मानपुर-मोहला में एक मुठभेड़ के बाद शव बरामद किया गया था। एसीएम रूपी बस्तर क्षेत्र में सक्रिय अंतिम तेलुगू माओवादी कैडर थी। मुठभेड़ स्थल की सर्चिंग के दौरान मृत महिला माओवादी के शव के साथ एक पिस्टल हथियार, गोला-बारूद और अन्य सामान बरामद किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से अभी भी इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है।

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि माओवादी कैडरों के सामने आत्मसमर्पण और पुनर्वास का अब भी मौका है। जो बचे हुए माओवादी हैं वो हथियार डाल दें। आईजी ने कहा कि बीते कुछ महीनों में काफी बड़ी संख्या में माओवादी कैडरों ने पुनर्वास का मार्ग अपनाया है। किंतु रूपी जैसे कुछ कैडरों ने पुनर्वास के मार्ग को छोड़कर हिंसात्मक रास्ता अपनाया।

ऐसे बदली नेलांगुर की तस्वीर, कभी खौफ का था साम्राज्य

■ नेलांगुर गांव के कई लोगों ने अपनी जिंदगी में पहली बार नलों से पानी आते देखा. दशकों तक नक्सली विकास की राह में रहे रोड़ा

नारायणपुर। माओवाद के बस्तर से पैर उखड़ते ही बदलाव की तस्वीर गांवों में दिखाई देने लगी है। महाराष्ट्र के बार्डर एरिया से लगे नेलांगुर में कभी माओवादियों की तूती बोलती थी। कदम-कदम पर माओवादियों ने यहां जमीन के नीचे मौत बिछा रखी थी। शाम होते ही खौफ का साम्राज्य यहां कायम हो जाता था। गोलियों और बमों के धमाकों से दहशत हो जाती थी। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन अब उसी नेलांगुर की तस्वीर तेजी से बदलने लगी है। ओरछा ब्लॉक में आने वाले नेलांगुर गांव में घर-घर जल जीवन मिशन का पानी पहुंचने लगा है। ओरछा ब्लॉक से करीब 52 किमी दूर नेलांगुर गांव में पीने का साफ पानी सप्लाई हो रहा है। पहले गांव के लोग पीने के साफ पानी के लिए दिन भर भटकते थे। कभी झिरिया तो कभी नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। कई बार तो बारिश के दिनों में पानी जनित बीमारियों के लोग शिकार भी हो जाते। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। गांव में पीने का साफ पानी आने लगा है। अबूझमाड़ जैसे जगहों में बुनियादी सुविधाओं का इजाफा ये बताता है कि अब नक्सलवाद और लाल हिंसा बीते दिनों की बात हो चुकी है।

कलेक्टर ने बताया कि जिला मुख्यालय नारायणपुर से लगभग 52 किलोमीटर दूर स्थित नेलांगुर के ग्रामीण लंबे समय से पेयजल संकट झेल रहे थे, लेकिन अब उनकी समस्या का समाधान होने से ग्रामीणों के लिए यह पहल राहत भरी साबित हो रही है। विशेष रूप से महिलाओं को अब दूर-दूर तक पानी लाने की परेशानी से मुक्ति मिली है। गांव में जल आपूर्ति शुरू होने से लोगों के दैनिक जीवन में सहजता आई है और स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। गांव के लोग भी ये समझने लगे हैं कि माओवादियों की वजह से वो दशकों तक अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं से महरूम रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी कहा है कि बस्तर के सभी गांवों तक बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाना सरकार का एकमात्र लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लगातार इसपर काम भी चल रहा है। जिला प्रशासन का कहना है, नेलांगुर में सोलर पंप आधारित जल आपूर्ति की यह पहल न केवल बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह क्षेत्र में विश्वास और विकास की नई नींव भी रख रही है।

बेलतरा एमएलए ने सिटी बस में किया सफर

■ 12 करोड़ से अधिक के कार्यों का शिलापूजन-लोकार्पण, बिलासपुर के ग्रामीण इलाके में लोगों को मिलेगी सुविधाएं

बिलासपुर। बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में रविवार को विकास उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 12 करोड़ 16 लाख 97 हजार की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलापूजन और लोकार्पण किया गया। विधायक सुशांत शुक्ला ने कोनी स्थित बस डिपो में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया। विधायक सहित जनप्रतिनिधियों ने सिटी बस की सवारी भी की। दरअसल, रविवार को विधायक सुशांत शुक्ला ने कोनी स्थित बस डिपो से सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आवागमन और अधिक सुगम होगा। सिटी बस सेवा को लेकर क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह देखा गया। सिटी बस सेवा का शुभारंभ के बाद विधायक सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, एमआईसी सदस्य और पार्षदों ने सिटी बस की सवारी की। बस में सवार होकर सभी जनप्रतिनिधि अपने अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। बस राजकिशोर पहुंची, जहां हरश्रृंगार कॉलोनी में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर विधायक शुक्ला ने कहा कि राजकिशोर नगर स्थित हरश्रृंगार सामुदायिक भवन से मध्यमवर्गीय परिवारों को सामाजिक आयोजनों के लिए सुलभ और किफायती जगह उपलब्ध होगा। सिटी बस सेवा रेलवे स्टेशन से गांधी चौक, तोरवा चौक, मोपका चौक, राजकिशोर नगर, साइंस कॉलेज, तिफरा, सकरी, बैमा, नगोई, पौंसरा, लखराम, अकलतरी, सरवनदेवरी होते हुए गढ़वट तक जाएगी।

मालगाड़ी की अचानक टूटी कपलिंग, 25 डिब्बे हुए अलग

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही। बिलासपुर-कटनी रेल सेक्शन पर रविवार शाम एक बड़ा रेल हादसा टल गया, जब पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन के पास कोयले से लदी एक मालगाड़ी अचानक दो हिस्सों में बंट गई। घटना से रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया।

जानकारी के मुताबिक, पेंड्रारोड और वेंकटनगर स्टेशन के बीच खैरझीटी बैरियर के पास अनूपपुर की ओर जा रही इस मालगाड़ी की कपलिंग अचानक टूट गई। इसके चलते इंजन से जुड़े लगभग 25 डिब्बे अलग होकर पीछे छूट गए। हालांकि समय रहते स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही कि लोको पायलट की सूझबूझ के कारण तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए गए। अगर लोको पायलट की नजर समय पर नहीं पड़ती, तो एक बड़े हादसे की संभावना थी।

तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे मालगाड़ी दो भागों में पटरी पर खड़ी है और रेलवे का तकनीकी अमला मौके पर पहुंचकर जांच में जुटा है। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद डिब्बों को सुरक्षित तरीके से दोबारा जोड़ा गया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कपलिंग टूटने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है। f

अवैध खनन पर कार्रवाई करने गए वन अमले को लाठी-डंडों से पीटा

मुंगेली। अवैध रेत खनन पर कार्रवाई करने गए वन अमले पर रेत माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे दो कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कलेक्टर कुंदन कुमार और डीएफओ अभिनव कुमार के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने स्नङ्कक दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पूरा मामला 10 अप्रैल 2026 की रात का है। वन विभाग के अफसरों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुंगेली जिले के खुड़िया वन परिक्षेत्र के सरगढ़ी परिसर में तैनात वन अमला अवैध रेत उत्खनन की सूचना पर जंगल की ओर बढ़ा था, उन्हें अंदाजा नहीं

था कि आगे उनके लिए जाल बिछाया जा चुका है। वन रक्षक अभिषेक बर्मन, योगेश बरेठ, देवेन्द्र बघेल और उनकी टीम जब भुक्खुनाला के पास पहुंची तो एक ट्रैक्टर अवैध रेत से भरा मिला। चालक राजकुमार यादव को मौके पर पकड़ लिया गया। सब कुछ नियंत्रण में लग रहा था, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। जैसे ही टीम जंगल के भीतर और ट्रैक्टरों की तलाश में आगे बढ़ी, कुछ वाहन अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। टीम ने एक और ट्रैक्टर को पकड़ा और वापस लौटने लगी, यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। भुक्खुनाला के पास अचानक कई लोग इकट्ठा हो गए। पहले बहस हुई, फिर गाली-गलौज और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। वन टीम को चारों तरफ से घेर लिया गया। ट्रैक्टर क्यों ले जा रहे हो इस सवाल के साथ शुरू हुआ विवाद हिंसक हमले में बदल गया। आरोपियों ने वनकर्मियों को न सिर्फ पीटा, बल्कि कुछ समय के लिए बंधक भी बना लिया। लाठी-डंडों, हाथ-मुक्कों से ताबड़तोड़ हमला किया गया। जान से मारने की धमकियां दी गईं। जंगल के बीच, अंधेरे में फंसी टीम के लिए हर पल खतरे से भरा था।

रायगढ़ के बटर फ्लाई में हुक्का पिलाते पकड़ाया मैनेजर

■ चॉकलेटी फ्लेवर तंबाकू के साथ हुक्का पॉट जब्त, जिले भर में कोटपा एक्ट के तहत 80 प्रकरण दर्ज

रायगढ़। रायगढ़ जिला के बटर फ्लाई गार्डन-रेस्टोरेंट की पुलिस ने जांच की। जहां हुक्का पिलाया जा रहा था। ऐसे में पुलिस ने मैनेजर पर कार्रवाई की है। साथ ही जिले भर में कोटपा एक्ट के तहत अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 80 प्रकरण दर्ज किए गए और हजारों का रुपये का जुर्माना लगाया है।

मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को पुलिस की टीम ने संबलपुरी रोड स्थित बटर फ्लाई गार्डन-रेस्टोरेंट में दबिश दी। जहां मौके पर रेस्टोरेंट मैनेजर चंदन कुमार पत्रो 39 साल द्वारा वहां आए लोगों को बिना वैध अनुमति सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के साथ तंबाकू युक्त सुट्टा हुक्का पिलाते पाया गया। ऐसे में पुलिस ने जांच के दौरान इससे संबंधित वैध दस्तावेज मांगा, लेकिन मैनेजर द्वारा कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका। तब पुलिस टीम के द्वारा मौके से दो नग हुक्का पॉट, दो नग सेंटर बेस, चार पैकेट चॉकलेटी फ्लेवर तंबाकू और एक पाइप कुल कीमती लगभग 8,000 रुपये का जप्त किया गया। मामले में चक्रधर नगर पुलिस ने आरोपी मैनेजर के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की। स्क्क शशि मोहन सिंह ने जिले भर में थाना-चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में जांच कर कोटपा एक्ट के तहत अभियान चलाने निर्देशित किया। जहां पुलिस की टीम ने बस स्टैंड, बाजार, शासकीय कार्यालय, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सघन जांच की गई। इस दौरान पान दुकानों पर तंबाकू उत्पादों के पैकेजिंग व स्वास्थ्य चेतावनी संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने पर संचालकों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। जांच अभियान के दौरान पुलिस ने 80 प्रकरण दर्ज किए। जिसमें सबसे अधिक तमनार क्षेत्र में कार्रवाई की गई। कोटपा एक्ट के तहत तमनार थाना क्षेत्र में 27 प्रकरणों में 5,400 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

रिटायर बिजली कर्मियों की ग्रेच्युटी से 20 लाख की धोखाधड़ी

कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी में एक बड़ा गबन सामने आया है। यह मामला सेवानिवृत्त नियमित कर्मचारियों की ग्रेच्युटी राशि से जुड़ा है। प्रारंभिक जांच में अब तक करीब 20.58 लाख रुपये के गबन की पुष्टि हुई है। तुलसी नगर सब स्टेशन कार्यालय में पदस्थ संविदा कर्मी हरीश कुमार पर आरोप है। उसने कार्यपालन अभियंता ईई (डी) से खाली चेक पर हस्ताक्षर कराए थे। बाद में हरीश ने चेक में अपना खाता नंबर भरकर रकम अपने खाते में जमा कर ली। इस तरह ग्रेच्युटी राशि संबंधित कर्मचारियों तक पहुंचने के बजाय सीधे आरोपित के खाते में चली जाती थी। यह मामला तब उजागर हुआ जब एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसकी राशि नहीं मिली। कर्मचारी की शिकायत पर किए गए मिलान में गड़बड़ी सामने आई। पुलिस ने आरोपित हरीश कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है, जिसमें निलंबन के साथ बर्खास्तगी की तैयारी है। संविदा कर्मी हरीश कुमार ने अपने बचाव में एक दावा किया है।

कबीरधाम में क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाते 2 गिरफ्तार

कबीरधाम। आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने और खिलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों लोग ऑनलाइन सट्टा खिलाने का जुर्म कर रहे थे। पुलिस को ये खबर मिली थी कि इलाके में कुछ लोग सट्टेबाजी में लगे हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। टीम ने एसपी के निर्देश पर डीएसपी भूपत सिंह के नेतृत्व में छापेमारी कर 2 लोगों को सट्टा खिलाते रंगेहाथों पकड़ा। पंडरिया पुलिस ने बताया कि सट्टेबाजों से जुड़ी जानकारी मुखबिर के जरिए पुलिस तक पहुंची। जिसके बाद पंडरिया के घोघरापारा इलाके में दबिश दी गई। पुलिस ने इलाके की पहले घेराबंदी की फिर बताए गए जगह पर रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस की गिरफ्त में आए 1 युवक का नाम महेंद्र ढीमर, उम्र 25 साल और दूसरे युवक का नाम सोनू राव, उम्र 31 साल है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे टेलीग्राम चैनल से सट्टा लिंक हासिल कर मोबाइल नंबर के जरिए आईडी बनाते थे। आईडी बनाने के बाद अपने बैंक खातों को उससे जोड़कर लेन-देन करते थे।

उरांव समाज ने पारंपरिक रुप से मनाया सरहुल पर्व

रामानुजगंज। रामानुजगंज विकासखंड अंतर्गत जामवंतपुर गांव में आदिवासी उरांव समाज ने प्रकृति की पूजा आराधना की। इस दौरान समाज ने लोकप्रिय सरहुल पर्व मनाया। इस दौरान उरांव समाज ने रैली भी निकाली। इसके बाद सरना स्थल की परंपरागत रूप से विधिवत पूजा की। ढोल मांदर की थाप पर पारंपरिक नृत्य भी किया। इस आयोजन के संबंध में उरांव समाज के प्रमुख ने बताया कि सरहुल पूजा हमारी है। हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति में जितने भी पौधे जो फल फूल देते हैं इसी से हमारे पूर्वज लोग इसी फल को खाकर जीवन बीताए हैं। पूर्वज पेड़ के नीचे रहा करते थे, उसकी पूजा करते थे। हमारी प्रकृति पूजा हमारे पेड़ पौधे ही हमारे जीवन को बचाए हुए हैं। आज भी उनका फल फूल हम खाते हैं उनकी पूजा करते हैं। आपको बता दें कि जामवंतपुर गांव में आयोजित सरहुल पूजा में बलरामपुर रामानुजगंज जिला सहित पूरे सरगुजा संभाग के उरांव समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। यही नहीं पड़ोसी राज्य झारखंड से भी बड़ी संख्या में जनजाति समाज के लोग इस पर्व को मनाते हैं।

फर्जी ई-चालान पर बलौदा बाजार पुलिस ने दी चेतावनी

बलौदा बाजार। अगर आपके भी मोबाइल पर अचानक आपका ई-चालान पेंडिंग है, तुरंत भुगतान करें जैसा कोई मैसेज आए, तो सावधान हो जाएं। यह मैसेज असली भी हो सकता है, लेकिन इन दिनों बड़ी संख्या में ऐसे फर्जी मैसेज भी भेजे जा रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ एक है, आपके बैंक खाते तक पहुंच बनाना और उसे एक झटके में खाली कर देना। इसी खतरे को देखते हुए बलौदा बाजार पुलिस ने आम लोगों के लिए खास चेतावनी जारी की है। पुलिस के मुताबिक, साइबर अपराधी अब ट्र-चालान के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं और नकली लिंक, वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए ठगी को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने बताया कि साइबर ठग सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजते हैं। इस मैसेज में लिखा होता है कि आपके वाहन का चालान कट चुका है और अगर तुरंत भुगतान नहीं किया तो भारी जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मैसेज में एक लिंक भी दिया जाता है, जो देखने में बिल्कुल असली सरकारी वेबसाइट जैसा लगता है।

उरपाजूर जंगल में भालू ने ग्रामीण के सिर पर किया अटैक

जगदलपुर। जिले के परतापुर थाना क्षेत्र के उरपाजूर जंगल में भालू ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इस घटना में एक ग्रामीण की जान चली गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई है। परतापुर थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्राम बड़े पराली बड़गांव निवासी सोनसाय आंचला अपने गांव के अन्य ग्रामीणों के साथ जंगल गया था। वे सभी सिहाड़ी रस्सी लेने के लिए उरपाजूर के जंगल में गए थे। जंगल में अचानक एक भालू ने सोनसाय पर हमला कर दिया। साथ गए कुछ ग्रामीण डरकर भाग निकले। अन्य ग्रामीणों ने सोनसाय को बचाने का प्रयास किया। लेकिन भालू ने सोनसाय के सिर को बुरी तरह नोंच लिया था। अत्यधिक खून बहने के कारण ग्रामीण सोनसाय की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन जंगल पहुंच गए। वन विभाग की टीम भी तत्काल मौके पर पहुंची। टीम लगातार जंगल में भालू की तलाश कर रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर जानलेवा हमला

■ ग्राम पचरी में शराब का अवैध धंधा करने वाले आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, सांकरा टीआई, प्रधान आरक्षक, महिला आरक्षक समेत कई घायल.

महासमुंद में रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने फेंके पत्थर

महासमुंद। जिले में शराब मामले के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हो गया।

मामला पटेवा थाना क्षेत्र के ग्राम पचरी का है। इस घटना में सांकरा टीआई उत्तम तिवारी के साथ प्रधान आरक्षक, महिला आरक्षक समेत कई लोगों को गंभीर चोटें आई है। मामले में आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने समेत कई धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। सांकरा टीआई उत्तम तिवारी ने पटेवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस टीम फरार आरोपी विजय मार्कंडेय एवं विनोद मार्कंडेय की गिरफ्तारी के लिए रवाना हुई। ग्राम पचरी में आरोपी के घर करीब 6 से 7 बजे के मध्य पहुंचने पर दोनों आरोपी भागने की कोशिश करने लगे। इस पर घेराबंदी कर पुलिस ने अभिरक्षा में लिया। लेकिन इसी बीच शासकीय वाहन में बिठाने का प्रयास किया गया तो दोनों आरोपी गाली गलौच करते हुए, मारपीट करने लगे। आस पड़ोस के लोगों और अपने रिश्तेदारों को चिल्लाकर आरोपियों ने बुलाया और पुलिस पर हमला करने के लिये उकसाने लगे।

आरोपियों के उकसावे में रिश्तेदार बहन हेमा, पिता छगन, चाचा गुलशन, दादी लीलाबाई, दादा गजेंद्र, विजय की पत्नी ज्योति, रिश्तेदार लक्की मार्कंडेय और कुछ पड़ोसी भी पुलिस पर हमला करने लगे। आरोपियों को बचाने और पुलिस टीम को भगाने के लिए लाठी डंडा और छड़ के टुकडे से मारपीट की गई। गली में पडे हुए ईंट, पत्थर के टुकड़ों से भी पुलिस बल पर हमला किया गया। जानलेवा हमले मे सांकरा थानेदार उत्तम तिवारी के सिर में, गले में और सीने में गंभीर चोट आई। साथ ही प्रधान आरक्षक अशवंत मन्नाडे और महिला आरक्षक को भी चोट आई है। पुलिस वाहन पर भी चारों तरफ से ईंट-पत्थर फेंके गए जिससे शीशा टूट गया। वहीं आरोपी की बहन हेमा पुलिस वाहन के सामने आकर रोड में लेट गयी। पत्थर लगने से हेमा के सिर में भी चोट लगी है। महिला आरक्षकों ने हेमा को उठाकर सुरक्षित स्थान पर छोडा।

सूरजपुर में घूसखोर कृषि विकास अधिकारी गिरफ्तार, एसीबी टीम ने रंगे हाथ दबोचा

■ सूरजपुर के कृषि विकास अधिकारी को एसीबी ने रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. आरोपी ने सेल्स मैनेजर से रिश्वत मांगी थी.

सरगुजा। सरगुजा संभाग में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूरजपुर कृषि विभाग के कृषि विकास अधिकारी को एक लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सोहनलाल भगत के रूप में हुई है, जो एक बीज कंपनी के सेल्स मैनेजर पर दबाव बनाकर रिश्वत की मांग कर रहा था। बताया जा रहा है कि हैदराबाद की एक बीज कंपनी में काम करने वाले सेल्स मैन अजीत कुमार कश्यप रीजनल एरिया में मक्का बीज सप्लाई का काम देखते हैं। उनसे ही कृषि विकास अधिकारी ने रिश्वत की मांग की थी। कंपनी ने सप्लाई किए गए बीज का कुछ स्टॉक बच जाने पर उसे अगस्त माह में एक कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा था। इसी दौरान कृषि विकास अधिकारी सोहनलाल भगत, जिन्हें बीज निरीक्षक का भी प्रभार मिला हुआ था। इस पर प्रार्थी ने एसीबी से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने ट्रैप प्लान तैयार किया।योजना के तहत प्रार्थी को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपये लेकर आरोपी के पास भेजा गया। जैसे ही सोहनलाल भगत ने राशि स्वीकार की, सतर्क एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम

रायपुर। गुरुकुल महिला महाविद्यालय की

एनएसएस यूनिट के द्वारा नारी शक्ति वंदन अभियान विषय पर जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं में महिलाओं के अधिकार, समानता एवं राजनीतिक भागीदारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉ. सांध्य गुप्ता प्राचार्य एवं विशिष्ट अतिथियों डॉ अदिति जोशी के स्वागत के साथ हुआ। इसके पश्चात अतिथि द्वारा इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई, जिसमें 33 प्रतिशत महिला आरक्षण, रोटेशन प्रणाली तथा इसके सामाजिक महत्व को सरल एवं प्रभावी ढंग से समझाया गया। छात्रों ने प्रभावशाली भाषण एवं समूह चर्चा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही, सभी उपस्थित छात्र-छात्राओं ने नारी सम्मान एवं समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए सामूहिक शपथ भी ली। विशिष्ट अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में डॉ रात्रि लहरी, डॉ मान्या शर्मा एवं स्वयं सेवक उपस्थित रहे।

पीएम सूर्य घर योजना से बने ऊर्जादाता बिजली बिल से मिली स्थायी राहत

रायपुर। केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। सरगुजा जिले के भगवानपुर निवासी संतोष सरकार इस परिवर्तन के उदाहरण हैं। उन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित कर न केवल बिजली बिल से पूर्णतः मुक्ति पाई है, बल्कि अब अतिरिक्त विद्युत उत्पादन कर ग्रिड को आपूर्ति करते हुए 'ऊर्जादाता' की भूमिका निभा रहे हैं। संतोष सरकार ने बताया कि सोलर पैनल स्थापना से पूर्व उन्हें प्रतिमाह 8 से 10 हजार रुपये तक का भारी बिजली बिल वहन करना पड़ता था, जिससे घरेलू बजट पर दबाव बना रहता था। योजना का लाभ लेने के पश्चात उनका बिजली बिल शून्य हो गया है, जिससे आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के अंतर्गत उन्हें कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की सब्सिडी स्वीकृत हुई है, जिसमें से केंद्र सरकार द्वारा 78 हजार रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से 30 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। संतोष सरकार ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना ने आम नागरिकों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने अन्य लोगों से भी इस योजना का लाभ लेने की अपील की है।

खैराखांडी व्यपवर्तन योजना के लिए 22.49 करोड़ रूपए स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा कोरिया जिले के विकासखण्ड-खडगंवा की खैराखांडी व्यपवर्तन योजना के कार्यों हेतु 22 करोड़ 49 लाख रूपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस व्यपवर्तन के निर्माण के पूर्ण होने से खरीफ सीजन में 400 हेक्टेयर तथा रबी सीजन में 165 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 565 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।

हरी खाद का उपयोग मिट्टी के लिए जीवनदायिनी संजीवनी से कम नहीं

रायपुर। हरी खाद मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, जैविक पदार्थ और नत्रजन (नाइट्रोजन) बढ़ाने के लिए उगाई जाने वाली दलहनी फसलें (जैसे-ढैंचा, सनई, मूंग, लोबिया) हैं, जिन्हें फूल आने से पहले खेत में ही जोतकर मिला दिया जाता है। यह मृदा की संरचना सुधारती है, नमी बनाए रखती है और रासायनिक खादों पर निर्भरता कम कर लागत घटाती है। हरी खाद का उपयोग मिट्टी के लिए किसी जीवनदायिनी संजीवनी से कम नहीं है। उर्वरता तेजी से घट रही धरती जो कभी सोना उगलती थी, आज थकान से बोझिल दिखने लगी है। रासायनिक उर्वरकों की अंधाधुंध दौड़ और लगातार सघन खेती ने मिट्टी की सेहत को भीतर तक कमजोर कर दिया है। ऐसे समय में कृषि विभाग ने किसानों के सामने एक सरल, सस्ता और टिकाऊ उपाय रखा है, हरी खाद, जो सिर्फ खेती नहीं, बल्कि धरती के पुनर्जन्म की कहानी लिख सकती है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे इस खरीफ सीजन से ही हरी खाद को अपनाएं। विभाग का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या और घटते जोत रकबा के कारण किसान एक ही खेत पर बार-बार खेती करने को मजबूर हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता तेजी से घट रही है। जैविक कार्बन और जरूरी पोषक तत्वों की कमी अब साफ दिखाई देने लगी है। हरी खाद केवल विकल्प नहीं, बल्कि टिकाऊ खेती की दिशा में निर्णायक कदम है।

कला हमेशा से अभिव्यक्ति, प्रतिबिंब और परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम रही: मंत्री साहेब

■ गौरा - राष्ट्रीय दृश्य कला प्रदर्शनी

रायपुर। गौरा में आपका स्वागत है। यह प्रदर्शनी आने वाले सभी लोगों के लिए खुशी, प्रेरणा और चिंतन का स्रोत बने। छत्तीसगढ़ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप द्वारा आयोजित तीसरी दृश्य कला प्रदर्शनी गौरा का आयोजन 10 से 12 अप्रैल 2026 तक महंत घासीदास संग्रहालय, राजभवन के निकट स्थित आर्ट गैलरी, रायपुर में किया जा रहा है। यह प्रतिष्ठित प्रदर्शनी देशभर के 100 प्रसिद्ध कलाकारों की कलाकृतियों को एक मंच पर प्रस्तुत करेगी। इस अवसर पर चार विशिष्ट अतिथि कलाकारों की सहभागिता भी रहेगी।

इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 10 अप्रैल 2026 को मुख्य अतिथि श्री गुरु खुशवंत, तकनीकी शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन व विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉ. चित्तरंजन कर , लेखक रायपुर और वेद प्रकाश भारद्वाज, दृश्य कलाकार, कला लेखक, क्यूरेटर और संपादक, नई दिल्ली के करकमलों द्वारा किया जाएगा, जो इस अवसर को गौरवान्वित करेंगे। उद्घाटन के पश्चात प्रदर्शनी दर्शकों के लिए खुली रही। गौरा प्रदर्शनी समकालीन भारतीय कला की विविधता, सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति का उत्सव है। यह कला प्रेमियों, विद्यार्थियों और आम दर्शकों को देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों की कृतियों को देखने और समझने का अनूठा अवसर प्रदान करेगी।

गुरु खुशवंत, तकनीकी शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ने कहा कि मुझे बेहद खुशी और गर्व है कि मैं छत्तीसगढ़ की जीवंत और विविध कलात्मक भावना के उत्सव, सीजीपीएजी की उद्घाटन प्रदर्शनी गौरा में आपका स्वागत करता हूँ। यह प्रदर्शनी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि इसमें हमारे क्षेत्र के 100 प्रगतिशील कलाकार एक साथ आ रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक ने हमारे सांस्कृतिक परिदृश्य के कैनवास पर अपनी अनूठी दृष्टि और रचनात्मकता का योगदान दिया है।

डॉ. ध्रुव तिवारी -क्यूरेटर, छत्तीसगढ़ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप रायपुर ने कहा कि कला हमेशा से अभिव्यक्ति, प्रतिबिंब और परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम रही है। गौरा के माध्यम से हमारा उद्देश्य छत्तीसगढ़ में मौजूद कलात्मक प्रतिभा के समृद्ध ताने-बाने को प्रदर्शित करना है, जो हमारे कलाकारों को अपनी कहानियों, सपनों और दृष्टिकोणों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह प्रदर्शनी केवल कलाकृतियों का प्रदर्शन नहीं है। यह एक संवाद है, कलाकार और दर्शक के बीच एक वार्तालाप है, जो आपको व्यक्तिगत स्तर पर कलाकृतियों का पता लगाने, व्याख्या करने और उनसे जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है।

घासीदास म्युजियम कला वीथिका रायपुर में की संगठनात्मक संरचना में डॉ. ध्रुव तिवारी -क्यूरेटर, जितेन साहू को-ऑर्डिनेटर, शांति तिर्की एसोसिएट को-ऑर्डिनेटर तथा अनिल खोबरागड़े, कोषाध्यक्ष के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ प्रस्तुत कृतियाँ हमारे कलाकारों के लचीलेपन, नवाचार और जुनून का प्रमाण हैं। वे हमारे समय के सार को पकड़ते हैं, उन विषयों को संबोधित करते हैं जो हमारी सामूहिक चेतना-पहचान, विरासत, पर्यावरण और मानवीय अनुभव के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। प्रत्येक कृति अपने निर्माता की आत्मा में एक खिड़की है, जो शब्दों से परे अंतर्दृष्टि और भावनाएँ प्रदान करती है।

डॉ. ध्रुव तिवारी ने बताया कि जब आप गौरा में आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको कलाकृतियों से न केवल दृष्टिगत रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। उन्हें आपसे बात करने दें, आपको चुनौती दें और आपको प्रेरित करें। कला में परिवर्तन लाने, विचार को उकसाने और समझ को बढ़ावा देने की शक्ति है। मुझे उम्मीद है कि यह प्रदर्शनी आप में से प्रत्येक के भीतर कला के लिए जिज्ञासा और प्रशंसा की चिंगारी को प्रज्वलित करेगी, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमें परिभाषित करने वाली रचनात्मक भावना से गहरा संबंध बनाएगी। डॉ. ध्रुव तिवारीने कहा कि मैं उन सभी कलाकारों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस प्रदर्शनी में अपने कामों का योगदान दिया है, साथ ही आयोजकों, प्रायोजकों और समर्थकों के प्रति भी जिन्होंने गौरा को संभव बनाया है। कला के इस उत्सव के पीछे आपकी लगन और जुनून प्रेरक शक्तियाँ हैं।

छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में पूरी होगी जनगणना, पूछे जाएंगे 33 सवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी जनगणना को लेकर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ और छत्तीसगढ़ जनगणना कार्य निदेशक कार्तिकेय गोयल ने पत्रकार वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। मनोज कुमार पिंगुआ ने बताया कि राज्य में जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का होगा, जो 1 मई से 30 मई 2026 तक चलेगा। इसके बाद दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना के रूप में आयोजित किया जाएगा।

बता दें कि इस बार देश में पहली बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तरीके से की जाएगी। नागरिकों को स्वयं ऑनलाइन जानकारी भरने का विकल्प भी मिलेगा। इसके लिए 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को स्ब्ध ब्रुष्ठ जनरेट की जाएगी। इसके बाद प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी का सत्यापन करेंगे।

गौरतलब है कि जनगणना के पहले चरण के दौरान घर-घर सर्वे कर लगभग 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें मकान की स्थिति, सुविधाएं और परिवार से जुड़ी जानकारी शामिल होगी। यह पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप में संपन्न की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि जनगणना कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के तहत

किया जाएगा और सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी। किसी भी कानूनी या जांच प्रक्रिया में इन आंकड़ों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

मकान से जुड़े सवाल

भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर, फर्श किस चीज का बना है, दीवार किस चीज की बनी है, छत किस चीज की बनी है, मकान का उपयोग (रहने, दुकान आदि), मकान की हालत कैसी है।

परिवार से जुड़े सवाल

घर का नंबर (परिवार के लिए), कुल कितने लोग रहते हैं, परिवार के मुखिया का नाम, मुखिया का लिंग (पुरुष/महिला/थर्ड जेंडर), मुखिया किस वर्ग से है (एससी/एसटी/अन्य), मकान अपना है या किराए का, परिवार के पास रहने के लिए कमरों की संख्या, कितने शादीशुदा जोड़े हैं।

सुविधा से जुड़े सवाल

पीने का पानी कहां से आता है, पानी की सुविधा घर में है या बाहर, बिजली/रोशनी का मुख्य साधन, शौचालय है या नहीं, शौचालय का प्रकार, गंदे पानी की निकासी कैसे होती है, नहाने की जगह है या नहीं, रसोई है या नहीं, एलपीजी/पीएनजी है या नहीं, खाना पकाने का मुख्य ईंधन, डिजिटल और सामान से जुड़े सवाल, रेडियो/ट्रांजिस्टर है या नहीं, टीवी है या नहीं, इंटरनेट सुविधा है या नहीं, लैपटॉप/कंप्यूटर है या नहीं, मोबाइल/फोन है या नहीं, वाहन और अन्य जानकारी, साइकिल/स्कूटर/बाइक है या नहीं, कार/जीप/वैन है या नहीं, परिवार कौन सा अनाज ज्यादा खाता है, मोबाइल नंबर (सिर्फ जनगणना के लिए)।

इन सभी सवालों की सही जानकारी देना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति गलत सूचना देता है या जनगणना कार्य में सहयोग नहीं करता है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत ऐसे मामलों में 1,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराए।

प्रदेश में जनगणना के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। लगभग 62,500 अधिकारी-कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी, जिनमें 47 जिला जनगणना अधिकारी, 250 जिला स्तरीय अधिकारी, 472 चार्ज अधिकारी, 1,160 मास्टर ट्रेनर, 51,300 प्रगणक और 9,000 पर्यवेक्षक शामिल हैं।

8 कार्यों के लिए 1.99 करोड़ स्वीकृत

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बिलासपुर जिले के बोदरी नगर पालिका में 8 कार्यों के लिए एक करोड़ 99 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री श्री अरुण साव ने सभी कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास ने बोदरी नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-7 में दो बी.टी. कोटिंग सड़कों के लिए 42 लाख 20 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। वार्ड क्रमांक-15 में बी.टी. कोटिंग सड़क के लिए 13 लाख 13 हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-11, 12, 13 एवं 14 में झूलेलाल मंदिर से दुर्गा मदिर तक बी.टी. कोटिंग सड़क के लिए 41 लाख 61 हजार रुपए तथा वार्ड क्रमांक-14 में आत्मानंद स्कूल से काली मंदिर होते हुए मेन रोड तक बी.टी. सड़क के लिए 16 लाख 73 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।

विभाग ने वार्ड क्रमांक-6 में रहंगी रोड से मुक्तिधाम तक सी.सी. रोड के लिए 31 लाख 8 हजार रुपए और वार्ड क्रमांक-10 में प्राथमिक शाला दड़हा से मेन रोड तक सी.सी. रोड के लिए 12 लाख 83 हजार रुपए मंजूर किए हैं। विभाग ने पीपल चौक से बिजली ऑफिस रहंगी मोड़ तक आर.सी.सी. नाली के निर्माण के लिए भी 41 लाख 50 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं।

रोजगार सहायक से वसूली के निर्देश, योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही का मामला

रायपुर। सरगुजा जिले की जनपद पंचायत उदयपुर के ग्राम पंचायत मुडग़ांव में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं महात्मा

गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मुडग़ांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के एक हितग्राही को मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत 90 मानव दिवस की मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं किया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि रोजगार सहायक श्री धनेश्वर प्रसाद यादव द्वारा कार्य पूर्ण होने के बावजूद मानव दिवस की प्रविष्टि समय पर ऑनलाइन नहीं की गई, जिसके कारण हितग्राही को देय मजदूरी राशि प्राप्त नहीं हो सकी।

उक्त लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा रोजगार सहायक श्री यादव के मानदेय से 21,871 रुपये की राशि वसूल करने के निर्देश दिए गए हैं। यह राशि आगामी पांच माह तक किश्तों में काटकर संबंधित हितग्राही को भुगतान की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी तथा दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गांव चलो अभियान के तहत जनसंवाद, समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर

रायपुर। जिले के ग्रामीण अंचलों में अधोसंरचना और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को नई दिशा देते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी.चौधरी ने रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। गांव चलो अभियान के तहत क्षेत्र के प्रवास पर पहुंचे वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और इसके लिए लगातार जमीनी स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं।

इस दौरान ग्राम-सूरजगढ़ में लगभग 192.92 लाख रुपये की लागत से निर्मित सूरजगढ़-पड़िगांव से तेलीपाली सड़क का लोकार्पण किया गया, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और यातायात सरल व सुगम होगा। वहीं ग्राम टिनमिनी में 12 लाख रुपये की लागत से शेड तथा 5.20 लाख रुपये की लागत से विक्रम घर से स्कूल तक सीसी रोड का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर कक्षा 12वीं की छात्रा अंजली सतपति को उनकी शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत नावापाली में 7.50 लाख रुपये की लागत से सांस्कृतिक शेड का लोकार्पण किया गया, जिससे ग्रामीणों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।

इसी क्रम में पड़िगांव में जगन्नाथ मंदिर के पास 7 लाख रुपये की लागत से निर्मित शेड का लोकार्पण किया गया। साथ ही यहां 20 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन तथा चौहान मोहल्ला में 10 लाख रुपये की लागत से शेड निर्माण कार्य का भूमिपूजन भी किया गया। ग्राम गुडू में वार्ड क्रमांक 01 में 10 लाख रुपये की लागत से बनी सीसी रोड का लोकार्पण किया गया, वहीं 10.40 लाख रुपये की लागत से बनने वाली एक अन्य सीसी रोड का भूमिपूजन किया गया।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने टिनमिनी सहित अन्य गांवों में गांव चलो अभियान के तहत चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इन कार्यों से न केवल बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, ग्राम के सरपंच, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

2025-26 में रिकॉर्ड 6000 किलोमीटर लंबे रेलवे विस्तार को मंजूरी मिली

समूचे देश को जोड़कर सबसे गरीब और दूरदराज के देशवासियों की सेवा कर रही है भारतीय रेल

रायपुर। देश के अंतिम छोर को जोड़कर और सबसे गरीब तथा वंचित क्षेत्रों की सेवा करते हुए, भारतीय रेल, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत एक परिवर्तनकारी विस्तार कर रही है। समावेशी विकास और राष्ट्रीय एकीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए, वित्त वर्ष 2025-26 में नई लाइनों, दोहरीकरण, मल्टी-ट्रैकिंग और अन्य कार्यों से जुड़ी 100 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह अभूतपूर्व प्रयास बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से विविध राष्ट्र को एकजुट करने के प्रति भारतीय रेल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही एक उच्च-क्षमता वाले और भविष्य के लिए तैयार नेटवर्क की नींव भी रख रहा है।

इन परियोजनाओं में कुल 1.53 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जो 6,000 किलोमीटर से अधिक के रेलवे नेटवर्क को कवर करता है। यह रेलवे विस्तार में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में, जहाँ 72,869 करोड़ रुपये की लागत वाली 64 परियोजनाओं (2,800 किलोमीटर से अधिक) को मंजूरी दी गई थी, इस बार परियोजना की स्वीकृतियों में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, रूट कवरेज में 114 प्रतिशत से अधिक का उछाल आया है और वित्तीय प्रतिबद्धता में 110 प्रतिशत से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

मंजूर की गई 100 परियोजनाओं में नई लाइनें, दोहरीकरण और मल्टी-ट्रैकिंग के काम, साथ ही बाईपास लाइनें, फ्लाईओवर और कॉर्ड लाइनें शामिल हैं। इनका रणनीतिक उद्देश्य भीड़भाड़ वाले मार्गों को खाली करना, समय की पाबंदी में सुधार करना और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना है, साथ ही उन क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी का विस्तार करना है जहाँ अभी तक पर्याप्त सुविधाएँ नहीं पहुँची हैं। इन पहलों से पूरे नेटवर्क में परिचालन दक्षता में काफी सुधार होने और यात्रा के समय में कमी आने की उम्मीद है।

ये परियोजनाएँ लगभग सभी प्रमुख राज्यों में फैली हुई हैं, जिससे रेलवे नेटवर्क का संतुलित और समावेशी विस्तार सुनिश्चित होता है। महाराष्ट्र (17 परियोजनाएँ), बिहार (11), झारखंड (10) और मध्य प्रदेश (9) प्रमुख फोकस राज्यों के रूप में उभरे हैं, क्योंकि माल ढुलाई गलियारों, औद्योगिक कनेक्टिविटी और यात्रियों की माँग में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में निवेश का पैमाना यात्री और माल ढुलाई, दोनों ही सेवाओं को काफी हद तक बेहतर बनाने वाला है।

महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इन परियोजनाओं से माल ढुलाई गलियारों को मजबूती मिलेगी, औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों की आवाजाही में सुधार होगा। ये राज्य भारत के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की रीढ़ हैं और यहाँ बेहतर कनेक्टिविटी होने से पूरी अर्थव्यवस्था में व्यापक लाभ होगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप, ये परियोजनाएं केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन को सक्षम बनाती हैं। जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार पर मुख्य ध्यान दिया गया है। छत्तीसगढ़ में रावघाट-जगदलपुर लाइन जैसी ऐतिहासिक पहल और झारखंड एवं ओडिशा में कई अन्य गलियारे, बाजारों, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे, जिससे वंचित आबादी को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाया जा सकेगा।

आर्थिक नजरिए से, यह विस्तार बड़े पैमाने पर और परिवर्तनकारी निवेश की दिशा में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाता है। 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 35 से ज्यादा परियोजनाएं कॉरिडोर-स्तर के अपग्रेड की आधारशिला हैं। प्रमुख परियोजनाओं में लगभग 10,150 करोड़ रुपये की लागत से कसारा-मनमाड तीसरी और चौथी लाइन (131 किमी), 8,740 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा 5वीं और 6वीं लाइन (278 किमी), 5,450 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से इटारसी-नागपुर चौथी लाइन (297 किमी) और 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सिकंदराबाद (सनतनगर)-वाडी तीसरी और चौथी लाइन (173 किमी) शामिल हैं। एकसाथ मिलकर, केवल ये परियोजनाएं 28,000 करोड़ रुपये की हैं, जो उच्च-घनत्व वाले ट्रंक रूटों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करती हैं।

ये परियोजनाएं रणनीतिक रूप से मिशन 3000 मीट्रिक टन पहल के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य माल ढुलाई क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि करना है। पोर्टफोलियो में ऊर्जा कॉरिडोर परियोजनाओं का दबदबा है, जो कोयले और खनिजों की तेज़ आवाजाही की सुविधा प्रदान करती हैं और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करती हैं। हाई डेंसिटी नेटवर्क परियोजनाएं महत्वपूर्ण मार्गों पर भीड़भाड़ को कम करती हैं, जबकि रेल सागर कॉरिडोर से पोर्ट कनेक्टिविटी और तटीय व्यापार में सुधार होता है। साथ मिलकर, ये पहलकदमियां समग्र नेटवर्क दक्षता और लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को बेहतर बनाएंगी।

इतने बड़े निवेश से बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा होने, स्टील और सीमेंट जैसे मुख्य क्षेत्रों में मांग बढने और पूरे देश में लॉजिस्टिक्स लागत कम होने की उम्मीद है। जैसे-जैसे ये परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी, रेलवे की क्षमता बढ़ेगी, सेवा वितरण में सुधार होगा और भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेंगी। यह कोई मामूली प्रगति नहीं है, यह परियोजनाएं भारत की अगली आर्थिक छलांग का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

अमेरिका और इजराइल पर ईरान को रत्ती भर भरोसा नहीं?

सनत जैन

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहली बार अमेरिका और ईरान के बीच आमने-सामने वार्ता हुई। इस बातचीत को लेकर अमेरिका और ईरान के जो प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान पहुंचे थे, उनमें आपसी सहमति नहीं बन पाई। बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे यह बातचीत पूरी तरह से बेनतीजा रही। शनिवार को ईरान ने लेबनान पर हमले रोकने की शर्त रखी। अमेरिका ने इस पर चुप्पी साध रखी। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल की सीधी वार्ता में राजनीतिक, सेना और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका की ओर से ईरान द्वारा पेश किए गए मुद्दों के किसी एक पर ऐसी कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसे ईरान स्वीकार कर सके। अमेरिका का जो प्रतिनिधिमंडल आया था, वह भी हार्मोज को खोलने के लिए अड़ा रहा। अमेरिका के इस प्रस्ताव को ईरान के प्रतिनिधि मंडल ने नहीं माना। ईरान का कहना था, सारे मुद्दों पर एक साथ बातचीत हो। एक साथ निर्णय लिए जाएं। ईरान पहले भी इस बात को कह चुका था। वह युद्धविराम के पक्ष में नहीं है। वह चाहता है, स्थाई रूप से युद्ध रुके। जो भी विवाद के कारण हैं, उन्हें दोनों पक्ष आपस में मिलकर सुलझायें। पाकिस्तान में हुई इस वार्ता में सबसे बड़ा अड़ंगा इजराइल ने लगा रखा था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहु लेबनान को निशाने पर रखना चाहते थे। दोनों ही पक्ष अपना-अपना प्रेशर एक दूसरे पर बनाते रहे। इस बैठक में चीन और पाकिस्तान की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। यदि होती तो कुछ ना कुछ समझौते की राह निकलती। दोनों ही पक्ष इसे अपनी हार और जीत के रूप में देख रहे थे। पाकिस्तान मे हुई वार्ता बेनतीजा रही। इसकी मुख्य वजह अमेरिका और इजराइल का इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा युद्ध विराम की आड़ में धोखा किया है। ईरान के साथ भी कई बार धोखा हो चुका है। जिसके कारण ईरान इस बार पूरी तरह से सतर्क था। अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान पर जो संयुक्त रुप से हमला किया गया है, उसमें ईरान को बहुत अधिक नुकसान हुआ है, इससे इंकार भी नहीं किया जा सकता है। ईरान अब आर-पार की लड़ाई लड़ने में आ गया है। सौ सुनार की और एक लोहार की तर्ज पर इस समय ईरान का वार अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ा है। ईरान को अच्छी तरह से मालूम था, यह बातचीत बेनतीजा रहेगी। इसलिए उसने अपनी युद्ध की तैयारी में जरा भी कोताही नहीं बरती। ईरान विश्व को यह बताने से भी नहीं चूका, कि वह शांति के पक्ष में है। युद्ध विराम के बाद जब इजराइल ने लेबनान पर हमले किए, इसका जवाब ईरान ने हिजबुल्ला के माध्यम से इजराइल को देकर वहां पर भारी तबाही मचा दी है। जो राजनीति अभी तक अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के साथ कर रहे थे, वही फार्मूला अब ईरान ने भी अपना लिया है। अमेरिका इस युद्ध में बुरी तरह से फंसा हुआ है। अमेरिका युद्ध से बाहर निकलना चाहता है। इजराइल के दबाव में वह बाहर नही निकल पा रहा है। ऐसी स्थिति में संभावना व्यक्त की जा रही है, जल्द ही अमेरिका समझौता के लिए नए रास्तों की तलाश करेगा। अमेरिका में जिस तरह से महंगाई एवं बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे निपटने के लिए युद्ध बंद करना बहुत जरूरी हो गया है। इसके अलावा कुछ महीनो में अमेरिका में कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसके पहले ट्रंप को अपनी स्थिति को मजबूत करना है। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की जनता सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही है। उसके बाद अमेरिका और इजराइल के पास अन्य कोई विकल्प भी नहीं बचा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने जीवन की सबसे कठिन पारी को खेल रहे हैं। युद्ध बंद होने की दशा में उन पर अंतरराष्ट्रीय अदालत और इजराइल की अदालत में मुकदमा चलना तय है।

पाकिस्तान की मध्यस्थता से शांति समझौता रहा बेनतीजा

संजय गोस्वामी

पाकिस्तान की मध्यस्थता से शांति समझौता कराने की कोशिशों के बीच अमेरिका और ईरान ने इस्लामाबाद में बातचीत की। अमेरिकी का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने की , जबकि ईरानी वार्ताकारों की अगुवाई अगुआई ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ कर रहे हैं। दल में विदेश मंत्री अब्बास अराघची, भी हैं लेकिन यह वार्ता में सफलता मिलने की संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है

आज सारी दुनिया को मालूम है पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है आज कल सारे न्यूज़ चैनल में अमेरिका ईरान युद्ध के 11अप्रैल 26 के शान्ति वार्ता पर ध्यान केंद्रीत है जो पाकिस्तान फुले नहीं समा रहा है और ऐ दिखाने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान शान्ति का मैसेंजर है लेकिन हकीकत उल्टी है दरअसल पाकिस्तान हाल ही में अफगानिस्तान में हवाई हमले कर 400 से अधिक निर्दोष नागरिकों को मौत की नींद सुला दिया और इजराइल पर ऐ आरोप लगाना तर्कसंगत है कि बेरूत में बम बरसा रहा है निर्दोष नागरिकों की हत्या कर रहा है जबकी वहाँ हिजबुल्लाह एक आतंकी संघठन है लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बुधवार को हुए इजरायली हमले में अब तक कम से कम 254 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1100 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।जो मानता हूँ ठीक नहीं है लेकिन जब आंतकवादी को पनाह देने वाले और आतंकवादी गतिविधियों में हजारों की संख्या में खुद ही निर्दोष लोग जिसमें भारत भी है को धर्म के आधार पर मारते हैं तो क्या ऐ सही है यदि धर्म का आधार ही है तो अफगानिस्तान में क्यों निर्दोष लोगों को मारा गया ऐ सिर्फ और सिर्फ अपनी डफली अपना राग और अपने आतंकी छवि को एक सफेद झूठ की चादर से ढक रहें है पाकिस्तान और ईरान का सीमा विवाद क़ोई नया नहीं है 2 वर्ष पूर्व याद कीजियेगा 17 जनवरी 2024 को मंगलवार रात पाकिस्तान पर हुए ईरानी मिसाइल हमले में दो बच्चों की मौत और तीन अन्य के घायल होने के बाद पाकिस्तान और ईरान के राजनयिक संबंधों में दरार है। उस समय पाकिस्तान ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था और इस्लामाबाद में मौजूद ईरान के दूत के पाकिस्तान लौटने पर रोक लगा दी। उस समय इस्लामाबाद ने ईरान पर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने का आरोपलगाया, जबकि ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि मिसाइलों ने जैश अल-अदल नामक सशस्त्र समूह के दो ठिकानों को निशाना बनाया था।उस समय एक बयान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा गया था , यह गैर-कानूनी हरकत पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसका कोई भी औचित्य नहीं है। इसमें चेतावनी दी गई, पाकिस्तान इस गैर-कानूनी हरकत का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके परिणामों की पूरी ज़िम्मेदारी ईरान की होगी।अमेरिका भी कैसे पाकिस्तान के चंगुल में फंस गया ऐ भी उसकी वर्ड पावर की छवि को बहुत ही निचे बातचीत के टेबल तक ले गया ऐ उसके इतिहास में कभी नहीं हुआ की पाकिस्तान जैसे देश में जाकर शांति वार्ता के लिए मज़बूरी वश जाना पड़ा क्योंकि पहले जितने भी राष्ट्रपति हुए वो या तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, हमले का बदला या ईरान पर हमला कर कभी पीछे नहीं मुड़ा जहाँ तक ईरान में युद्ध की बात है नाटो का कहना ऐ उसका निजी मामला है हमसे पूछ कर नहीं किया गया तो ईराक में जब सद्दाम हुसैन पर हमला किया गया तो किससे पूछ कर किया फिर भी वहाँ भी अमेरिका को क्या खतरा था ईरान से तो समझ में आता है कि अमेरिका को बाद में खतरा हो सकता था क्योंकि उसकी मिशायल की मारक क्षमता बाद में अमेरिका तक मार करने की क्षमता हासिल कर सकता था और जो अभी खाड़ी देशों में अमेरिका के बेस पर जिसतरह हमला हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ ऐ अमेरिका को गहरा चोट पहुँचाया है और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी मिली भगत हैं क्योंकि उसी के बॉडर से होकर ही हथियार गया है जो अमेरिका के लाख बम्रबारी के बाद भी 100 वीं लहर तक कैसे गया इसलिए की इसमें चीन और रूस के साथ पाकिस्तान का भी हाथ होगा हथियार पहुंचाने में, जो खबर निकल कर सामने आई है इसलिए पाकिस्तान शान्ति वार्ता क्या कराएगा जो खुद ही आतंकवादी के सहारे दहशतगर्द को पनपा रहा है और भारत में मासूमों की हत्या करवाता है 26/11/08 को मुंबई में पाकिस्तान के आईएसआई ने ऐसी कत्लेआम का अंजाम दिया जिसमें सैकड़ो मासूमों की जान चंद आतंकवादी ने कत्लेआम किया वो भी धर्म के नाम पर, और हाल ही में पहलगांव में दर्जनों भारतीय पर्यटक की हत्या धर्म के नाम पर की, अत: एक कहावत है जो संत कबीर ने लिखी है ^-बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय,संत कबीरदास जी का यह प्रसिद्ध दोहा आत्म-निरीक्षण (ह्यद्ग्घ्द्ध-ह्द्ग्द्धद्यद्ग्ष्ह्लद्बश्ठ्ठ) का संदेश देता है, जो सिखाता है कि दूसरों में दोष ढूंढने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। भारत अगर ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला नहीं करता तो कट्टरवादी आतंकी फिर क़ोई नया खेल करते और भारतीय मासूमों की जान जाती किसी भी धर्म में मानवता को ही सर्वोपरि माना गया है लेकिन धर्म की आड़ लेकर लोग इसका फायदा आतंक को पनपाने में करता है जो विश्व के लिए खतरा है अब ईरान भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है क्योंकि जिस तरह खाड़ी देशों में उसके हमले में कई निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है और जिस तरह हार्मोस को पूरी तरह बंद करके दूसरे देश के लिए क्यों बन्द किया जिसका इस युद्ध से क़ोई लेना देना नहीं है और उसने इसे सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। तेहरान ने छोटी नावों का इस्तेमाल करके हार्मोज में माइंस बिछा दी जिससे क़ोई भी जहाज इसका शिकार हो सकता है जिससे इस युद्ध में क़ोई लेना देना नहीं है कई जहाजो को वहाँ से गुजरने पर उड़ा भी दिया गया ऐ सब विश्व शांति के लिए खतरा है, और आतंकवादी देश आतंकी देश ही आपस में तालमेल बिठा लेते हैं और आतंकी को पनपाने में अमेरिका का ही हाथ रहा है क्योंकि यह बात खुद ट्रम्प ने ही पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को ईरान में परमाणु समझौता किया जिससे वो आज परमाणु बम बनाने के तरफ कदम रखा, हुती हिजबुल्ला, हमास, मलेशिया ग्रुप ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हैं जो न सिर्फ इजराइल में बल्कि मिडिल ईस्ट में आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम देते हैं ट्रम्प की हताशा यहाँ तक हो गई थी की सभ्यता नष्ट की बात करते हैं और फिर शान्ति के मसीहा बन जाते हैं और ईरान में अपने पैर पसारने और सजाने संवारने की बात करते हैं वहीँ ईरान में कहाँ परिवर्तन हुआ आज भी खामनोई का फोटो और झंडा लहराते हुए लोग जश्न मानते नजर आ रहें हैं युद्ध विराम किया अच्छी बात है लेकिन पहले डराने धमकाने और ख़त्म करने का धमकी देने की जरुरत क्या थी ईरान ने अमेरिका को आर्थिक और सामरिक दृश्टिकोण से अपने मिशायल से काफी नुकसान पहुँचाया है और खाड़ी देश से अमेरिका के बेस को इस तरह बर्बाद किया है कि उन देशों पर अमेरिका का भरोसा उठ गया है और ऐ युद्ध इजराइल के लिए ख़त्म नहीं हुआ है आज भी बेरूत में हिजबुल्ला पर अटैक कर ही रहा है। इसलिए ऐ सीजफायर ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता मात्र एक दिखावा है क्योंकि ईरान का भरोसा खाड़ी में अपने परोसी देशों पर हमला करना और इजराइल ने साफ कहा है कि शांति वार्ता में ऐ युद्ध शामिल नहीं है और इजराइल का समर्थन ट्रम्प ने किया है तभी युद्ध हुआ और अब अमेरिका कुछ दिन युद्ध विराम कर इससे सबक लेते हुए आगे की सैन्य अभियान को दुरुस्त करने की है क्योंकि इसमें कई पेंच है जो इजराइल के पास येरुशेलम को लेकर एक धार्मिक स्थल है जो 2017 में डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बयान में साझा किया था कि यरूशलम न केवल तीन महान धर्मों का केंद्र है, बल्कि अब यह दुनिया के सबसे सफल लोकतंत्रों में से एक का भी केंद्र है। पिछले सात दशकों में, इज़राइल के लोगों ने एक ऐसा देश बनाया है जहाँ यहूदी, मुसलमान, ईसाई और सभी धर्मों के लोग अपनी अंतरात्मा और अपनी मान्यताओं के अनुसार रहने और पूजा-अर्चना करने के लिए स्वतंत्र हैं। यरूशलम आज भी एक ऐसा स्थान है—और हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए—जहाँ यहूदी वेस्टर्न वॉल पर प्रार्थना करते हैं, जहाँ ईसाई स्टेशन्स ऑफ़ द क्रॉस पर चलते हैं, और जहाँ मुसलमान अल-अक्सा मस्जिद में इबादत करते हैं।जहाँ अमेरिका के रक्षा मंत्री हेगसेथ का कहना है कि यरूशलम का इतिहास क्रूसेड्स—मध्ययुग के उन क्रूर युद्धों—का बचाव करने का रहा है, जिनमें ईसाई और मुसलमान एक-दूसरे के खिलाफ लड़े थे। अपनी 2020 की किताब अमेरिकन क्रूसेड में, उन्होंने लिखा कि जो लोग पश्चिमी सभ्यता का आनंद लेते हैं, उन्हें किसी क्रूसेडर का शुक्रिया अदा करना चाहिए।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

जब कि देवसमाज ने विश्वरूप को शत्रु पक्ष का सम्बन्धी जानते हुए भी विश्वासपूर्वक पौरोहित्य जैसे दायित्वपूर्ण पद पर अभिषिक्त कर दिया था, और वे सब उसे देवगुरु मानकर हर तरह से उस पर सर्वस्व न्योछावर करने को प्रस्तुत थे, तब यज्ञ समय में देवताओं का स्वत्व छीनकर चोरी 2 से दैत्यों को दे डालना--महाविश्वासघात नहीं तो भौर क्या है ? ऐसी दशा में विश्वासघातपूर्वक देवसत्ता की जड़ खोखली करने वाले पापिष्ठ पुरुष को मार डालना किस आधार परं अधर्म कहा जा सकता है? वेद में स्पष्ट लिखा है कि-

शत्रोर्मूर्धानं विश्वग्भिन्धि।

(अथर्व 3।6।6)

अर्थात् - शत्रु के शिर को सब तरह से तोड़ डाल।

इसी प्रकार स्मृतियों में भी आततायी को तत्काल मार डालना लिखा है। सो विश्वरूप, विश्वास घातपूर्वक देवताओं के जीवन-सर्वस्व हव्य का अपहरण करने वाला होने के कारण आततायी ही कहा जा सकता है। अत: इन्द्र का यह आचरण सर्वथा न्याययुक्त है। यही प्रथम आक्षेप का उत्तर है। इतने पर भी जो इन्द्र ने स्वेच्छा से %ब्रह्महत्या% को स्वीकार किया है वह उसकी शिष्टता एवं मानव-मर्यादा-दक्षता का आदर्श है जो उसके देवराजपद के सर्वथा अनुकूल है। इसके अतिरिक्त शङ्कावादी महाशय ने जो इस आख्यान पर तीन सिर आदि के उल्लेख से असम्भवता का दोष लगाया है वह भी व्यर्थ है। क्योंकि केवल पुराणों में ही तीन सिरों का उल्लेख नहीं है किन्तु वेद में भी साफ शब्दों में इसे त्रिशीर्षा, षडक्ष: और त्रीणि एव मुखानि आसन कहते हुये तादृश बतलाया है, अत: जो समाधान वैदिक-स्वरूप का होगा वही पौराणिक का भी समझ लेना चाहिये।

क्रमश: ...

डॉ. भीमराव अंबेडकर

दिलीप कुमार पाठक

प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल का सूर्य जब भारतीय क्षितिज पर उदय होता है, तो वह केवल एक महापुरुष की जन्मतिथि का संदेश नहीं लाता, बल्कि उस महान संकल्प का स्मरण कराता है जिसने आधुनिक भारत की नियति लिखी थी। डॉ. भीमराव अंबेडकर - एक ऐसा नाम, जो आज भारतीय जनमानस की चेतना में गहराई तक रचा-बसा है। देश के हर कस्बे और चौराहे पर उनकी प्रतिमाएं जीवंत हैं, नीले झंडे लहरा रहे हैं और जयकारों के स्वर आसमान छू रहे हैं। लेकिन, इस भव्य उत्सव और कोलाहल के बीच एक अत्यंत गंभीर और चुभता हुआ प्रश्न मौन खड़ा है क्या हमने वाकई उस इंसान को समझा, जिसने अपना पूरा जीवन न्याय, समता और मानवता की वेदी पर होम कर दिया? या फिर हमने अपनी सुविधा और संकुचित सोच के अनुसार उनकी विरासत के टुकड़े-टुकड़े कर दिए हैं?

डॉ. अंबेडकर की शख्सियत का असली करिश्मा उनकी अद्भुत विद्वत्ता, फौलादी इरादों और सबसे बढ़कर उनके अडिग नैतिक साहस में छिपा था। वे केवल एक संविधान निर्माता या कानूनविद नहीं थे; वे एक ऐसे युगद्रष्टा थे जिनके पास भविष्य के भारत का पूर्ण खाका तैयार था। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षित उस व्यक्ति के पास दुनिया के किसी भी कोने में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने के विकल्प खुले थे, लेकिन उन्होंने उस कांटों भरे मार्ग को चुना जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की मुक्ति की ओर जाता था। उनके व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक अपमान के अनगिनत गहरे घाव थे, लेकिन जब उन्हें देश का भाग्य लिखने की कलम मिली, तो उन्होंने बदला नहीं, बल्कि बदलाव की इबारत लिखी। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की नींव रखी जहाँ किसी के साथ भी अन्याय न हो—चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का क्यों न हो। किन्तु, कड़वा सच तो यह है कि बाबा साहब की विराट विरासत के साथ सबसे बड़ा अन्याय यह हुआ कि उन्हें जातियों के खांचों में कैद करने की निरंतर कोशिश की गई। समाज का एक बड़ा हिस्सा उन्हें केवल एक विशिष्ट समुदाय का मसीहा मानकर अपनी भावनात्मक सीमाओं में सीमित कर बैठा। उन्होंने बाबा साहब को पूजा तो सही, लेकिन उनके उन तार्किक और प्रगतिशील विचारों को आचरण में नहीं उतारा जो अंधविश्वास और रूढ़ियों के कट्टर विरोधी थे। दूसरी ओर, मुख्यधारा के एक बड़े वर्ग ने दशकों तक उन्हें केवल दलितों का नेता मानकर उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखी। यह बौद्धिक दरिद्रता ही थी कि समाज यह नहीं समझ पाया कि डॉ. अंबेडकर द्वारा दिलाए गए अधिकार सार्वभौमिक थे। जब उन्होंने हिंदू कोड बिल के लिए अपनी कैबिनेट की कुर्सी दांव पर लगाई, तो उनका लक्ष्य समूचे भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाना था। अफसोस कि उन्हें एक पक्ष ने सिर्फ अपना माना और दूसरे ने पराया, जबकि वास्तविकता में वे पूरे राष्ट्र के थे।

आज की समकालीन राजनीति में डॉ. अंबेडकर एक अनिवार्य प्रतीक बन चुके हैं। सत्ता की बिसात पर हर राजनीतिक दल उन्हें अपना बताने की होड़ में है, लेकिन यह लगाव सिद्धांतों से ज्यादा वोटबैंक के गणित से प्रेरित है।

ईरान-अमेरिका-पाकिस्तान त्रिकोणीय कूटनीति

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर पश्चिम एशिया में हालिया 14 दिन के युद्धविराम के बाद दुनियाँ की नजरें अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर टिक गई हैं, जहां ईरान और अमेरिका के बीच 11 अप्रैल 2026 पर टिक गई है जहाँ उच्च स्तरीय वार्ता चल रही है। यह वार्ता केवल एक कूटनीतिक प्रक्रिया नहीं,बल्कि वैश्विक शक्ति- संतुलन,ऊर्जा सुरक्षा,क्षेत्रीय स्थिरता और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुकी है।खास बात यह है कि पाकिस्तान इस पूरी प्रक्रिया में एक मध्यस्थ और मेजबान की भूमिका निभा रहा है,जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक संकेत है। यह वार्ता फिलहाल द्विपक्षीय (बाइलेटरल) स्तरपर चल रही है,लेकिन संभावनाएं इस बात की हैं कि यह आगे चलकर त्रिपक्षीय (ट्राइलेटरल) रूप ले सकती है, जो वैश्विक कूटनीति में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। मैं यह मानता हूं कि इस वार्ता की मेजबानी कर रहे शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर की उपस्थिति यह दर्शाती है कि पाकिस्तान इस अवसर को अपनी कूटनीतिक साख बढ़ाने के रूप में देख रहा है। विदेश मंत्री इशाक डार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद असीम मलिक भी इस वार्ता में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि वह खुद को एक जिम्मेदार मध्यस्थ के रूप में स्थापित करे,जैसा कि अतीत में कतर या नॉर्वे ने किया था,हालांकि यह भूमिका जोखिम से खाली नहीं है, क्योंकि किसी भी विफलता का असर उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि पर पड़ सकता है।

साथियों बात अगर हम वार्ता का प्रारूप- बाइलेटरल से ट्राइलेटरल की ओर? इसको समझने की करें तो फिलहाल बातचीत अलग-अलग चैनलों के जरिए हो रही है, पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के साथ अलग-अलग संवाद कर रहा है।यह शटल डिप्लोमेसी का एक क्लासिक उदाहरण है।अगर दोनों पक्षों की प्रमुख मांगें पूरी हो जाती हैं, तो यह वार्ता त्रिपक्षीय रूप ले सकती है। लेकिन यह प्रक्रिया बेहद जटिल है, क्योंकि तीनों देशों के हित और प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं।पाकिस्तान के लिए यह अवसर है,अमेरिका के लिए रणनीतिक संतुलन और ईरान के लिए अस्तित्व और सम्मान का सवाल।

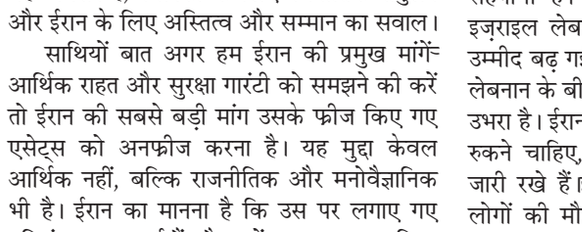

साथियों बात अगर हम ईरान की प्रमुख मांगें- आर्थिक राहत और सुरक्षा गारंटी को समझने की करें तो ईरान की सबसे बड़ी मांग उसके फ्रीज किए गए एसेट्स को अनफ्रीज करना है। यह मुद्दा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक भी है। ईरान का मानना है कि उस पर लगाए गए प्रतिबंध अन्यायपूर्ण हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए। हालांकि, व्हाइट हाउस ने इस पर स्पष्ट संकेत दिया है कि फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।इसके अलावा ईरान ने लेबनान में सीजफायर को भी वार्ता का हिस्सा बताया है, जो इस बात का संकेत है कि वह इस बातचीत को क्षेत्रीय संदर्भ में देख रहा है, न कि केवल द्विपक्षीय मुद्दे के रूप में हैं

ईरान इस वार्ता में पूरी तरह बिना भरोसे के प्रवेश कर रहा है। इसका कारण है अतीत में अमेरिका द्वारा किए गए वादों का टूटना,विशेषकर ईरान परमाणु समझौता 2015 से अमेरिका का बाहर निकलना। यह अविश्वास वार्ता को जटिल बनाता है, क्योंकि किसी भी समझौते के लिए विश्वास का होना अनिवार्य है। ईरान की शर्तें स्पष्ट हैं पूर्ण युद्धविराम,नुकसान की भरपाई और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही। यदि ये शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो वार्ता के टूटने की संभावना बनी रहेगी।

साथियों बात अगर हमअमेरिका का दृष्टिकोण- रणनीतिक नियंत्रण और संतुलन को समझने की करें तोअमेरिका की प्राथमिकता है कि ईरान एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में उभर न सके। इसके लिए वह आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक दबाव और सैन्य उपस्थिति का उपयोग करता रहा है। जेडी वेंस की इस्लामाबाद यात्रा और उनकी चेतावनी इस बात का संकेत है कि अमेरिका इस वार्ता को केवल शांति प्रक्रिया नहीं, बल्कि रणनीतिक उपकरण के रूप में देख रहा है। अमेरिका के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि इज़राइल की सुरक्षा सुनिश्चित रहे, जो उसका प्रमुख सहयोगी है। इस्लामाबाद में हो रही बातचीत से इज़राइल लेबनान संघर्ष- वार्ता पर संकट छाने की उम्मीद बढ़ गई है, इस पूरे परिदृश्य में इज़राइल और लेबनान के बीच जारी संघर्ष एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि लेबनान में हमले रुकने चाहिए, जबकि इज़राइल ने अपने ऑपरेशन जारी रखे हैं।इस संघर्ष में एक ही दिन में सैकड़ों लोगों की मौत की खबरें आई हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाती हैं। यह संघर्ष न केवल मानवीय संकट पैदा कर रहा है, बल्कि शांति वार्ता को भी प्रभावित कर रहा है।

साथियों बात अगर हम दिनांक 11 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में ईरान-अमेरिका संभावित स्थाई शांति संबंधी हो रही बैठक की करें तो आगे की बातचीत के लिए ट्रंप ने सस्पेंस बरकरार रखा है,उन्होंने पिछली अमेरिकी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग 47 साल से सिर्फ बातें ही कर रहे थे,उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि कल की मीटिंग ही यह तय करेगी कि आगे क्या होगा. ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि यह आखिरी मुलाकात होगी या आगे भी दौर चलेगा, बस इतना कहा कि हमें देखना होगा कि कल क्या नतीजा निकलता है, इस्लामाबाद वार्ता से ठीक पहले ईरान के उपराष्ट्रपति ने अमेरिका को बेहद सख्त और सीधा संदेश भेजा है. ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर वे अमेरिका फर्स्ट के प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, तो एक ऐसी डील मुमकिन है जो दोनों देशों और दुनियाँ के लिए फायदेमंद हो लेकिन,अगर अमेरिका इजरायल फर्स्ट की सोच के साथ मेज पर आता है,तो कोई समझौता नहीं होगा. ईरान ने चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ अपनी रक्षा जारी रखेंगे,जिसका खामियाजा पूरी दुनियाँ को भुगतना होगा पूरा विश्व उम्मीद कर रहा है कि इस्लामाबाद में हो रही ईरान अमेरिका की बैठक सफल हो ताकि पूरे विश्व के शेयर बाजारों और नागरिकों को वित्तीय क्राइसिस से सटिका से बचाए जा सके।

साथियों बात अगर हम आने वाले 14 दिन और इस्लामाबाद में 11 अप्रैल 2026 को हुई बैठक-निर्णायक मोड़ साबित होगी इसको समझनें की करें तो,सीज़फायर केवल 14 दिनों का है,और यही अवधि वैश्विक बाजारों की दिशा तय करेगी।(1)संभावित परिदृश्य-(अ)यदि शांति बनी रहती है,तेल कीमतें स्थिर रहेंगी,बाजार में और तेजी आएगी(ब)यदि तनाव फिर बढ़ता है- तेल कीमतों में उछाल, बाजार में गिरावट (2)मध्य मार्ग- अस्थिरता बनी रहेगी, निवेशक सतर्क रहेंगे,इसलिए संभवत: अनिश्चितता के बीच अवसर अप्रैल 2026 का यह सप्ताह यह दर्शाता है कि वैश्विक बाजार कितने संवेदनशील और गतिशील हैं। ईरान-अमेरिका सीज़फायर ने यह साबित किया कि एक सकारात्मक भू- राजनीतिक घटनाक्रम किस प्रकार पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।भारत के संदर्भ में, यह सप्ताह एक सकारात्मक संकेत लेकर आया है मजबूत घरेलू मांग, निवेशकों का बढ़ता विश्वास, और वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद स्थिरता की ओर बढ़ता बाजार।हालांकि, अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। आने वाले 14 दिन न केवल पश्चिम एशिया की राजनीति, बल्कि वैश्विक आर्थिक दिशा भी तय करेंगे।

साथियों बातें कर हम ऊर्जा संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर को समझने की करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग बाधित होने से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। यह मार्ग दुनियाँ के लगभग 20 प्रतिशत तेल व्यापार का केंद्र है।

आज का इतिहास

1871 कनाडा ने डॉलर, सेंट, और मिल्स के रूप में मुद्रा का संप्रदाय निर्धारित किया।
1872 सैन फ्रांसिस्को बार एसोसिएशन का आयोजन किया गया।
1900 पेरिस विश्व प्रदर्शनी खुली।
1906 20 वीं शताब्दी में फैलोफ पेंटेकोस्टेलिज्म के लिए प्राथमिक उत्प्रेरक अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल, लॉस एंजिल्स में खोला गया।
1909 संवैधानिक सरकार के खिलाफ एक सैन्य विद्रोह के बाद, एक भीड़ ने अडानी विलायत, ओटिकन साम्राज्य में आर्मेनियाई लोगों का नरसंहार शुरू किया।
1916 इंपीरियल जर्मन सेना ने उत्तरी तट पर हमले से बचाने के लिए ने तटीय रक्षा के उच्चायुक्त की स्थापना की।
1933 सेप्टिमियस सेवेरस ने पांच बादशाहों के वर्ष के दौरान पेर्टिनैक्स की मृत्यु के बाद रोमन साम्राज्य के सिंहासन को जब्त कर लिया।
1935 एक भारी धूल तूफान ओक्लाहोमा और उत्तरी टेक्सास में बह गया, अनुमानित 300,000 लघु टन (270,000 टी) टॉपसाइल को हटा दिया।
1954 ऐशूरिन बेवन ने ब्रिटिश लेबर पार्टी के छाया कैबिनेट से इस्तीफा दिया।
1978 जॉर्जियाई एसएसआर के सर्वोच्च सोवियत द्वारा जॉर्जियाई भाषा की संवैधानिक स्थिति को बदलने के लिए हज़ारों जॉर्जियाई लोगों ने त्बिलिसी में प्रदर्शन किया।
1980 आयरन मेडेन का पहला आत्म-शीर्षक एल्बम आयरन मेडेन प्रकाशित किया गया।
1981 पहला अंतरिक्ष यान कोलंबिया-1 वापस धरती पर लौटा।
1985 49 वीं गोल्फ मास्टर्स चैंपियनशिप- बर्नहार्ड लैंगर ने जीत दर्ज की, 282 की शूटिंग की।
1988 मेल्स म्यूजिक बॉक्स थियेटर न्यूयॉर्क सिटी में खुलता है। यह 36 प्रदर्शनों के लिए था।
1992 बेक एंड डॉल्स मार्टिन बेक थिएटर न्यूयॉर्क सिटी में खुलता है। यह 1,143 प्रदर्शनों के लिए था।
1994 ऑपरेशन प्रोवाइड कम्फर्ट इन्नोरसेंट इराक के दौरान एक दोस्ताना आग की घटना में, दो अमेरिकी वायु सेना के विमानों ने गलती से दो यूएसआरमी हेलीकॉप्टर को गोली मार दी, जिसमें 26 लोग मारे गए।
1999 मलेशिया के अपदस्थ उपप्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को भ्रष्टाचार के मामले में छह वर्ष क़ैद की सज़ा।
2000 रूस की संसद ने संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच स्टार्ट-2 परमाणु शस्त्र कटौती संधि का अनुमोदन किया।

युद्धविराम में पाकिस्तान तो सिर्फ मोहरा, असली किंगमेकर चीन

सौरभ वार्ष्णेय

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव न केवल पश्चिम एशिया की स्थिरता के लिए खतरा है, बल्कि दक्षिण एशिया के देशों, विशेषकर पाकिस्तान, के लिए भी एक कठिन कूटनीतिक की परीक्षा बनकर रह गया है। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति, उसकी सैन्य-रणनीतिक अहमियत और इस्लामी देशों के साथ उसके रिश्ते इस संकट में उसकी भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बना देते हैं। वहीं चीन की चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति है। वह सीधे मंच पर आने के बजाय पर्दे के पीछे से प्रभाव डालकर अपने हितों को सुरक्षित रखना चाहता है। अगर ऐसे में युद्धविराम दो हफ्ते की वजाह पूरी तरह से सफल हो जाता है इसमें चीन का ही फायदा होगा? क्योंकि फिर से अमेरिका तेल ऊर्जा की महाशक्ति बनते बनते रह जायेगा?

आज अमेरिका -ईरान के बीच भले ही दो हफ्ते का युद्ध विराम हो गया है लेकिन पूरी तरह से हो गया है यह कहना बेईमानी होगी? युद्धविराम का अर्थ है कि शांति ? अमेरिका-ईरान-इजरायल युद्ध पश्चिम एशिया के लिए ही नहीं बरन पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा संकट को खतरा बढ़ गया वहीं दक्षिण एशिया के देशों, विशेषकर पाकिस्तान, के लिए भी एक कठिन कूटनीतिकार की भूमिका में ला खड़ा किया। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति को देखा जाये तो उसकी सैन्य-रणनीतिक अहमियत और इस्लामी देशों के साथ उसके रिश्ते इस संकट में उसकी भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि इसके पीछे असली दिमाख तो चीन का लगा है। यानी जैसे अमेरिका खुद न लड़कर दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है वैसे ही पैंतरा चीन ने सीख लिया। चीन ने भी पाकिस्तान को मोहरा बनाकर इस संकट से उबरने के लिए उसे अपना मोहरा बनाया। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि अमेरिका का सब जानता न हो ? लेकिन इस समय इजरायल के जाल में फंसकर जैसा कि इजरायल शुरु से चाहता है कि ईरान का नेस्तानूबूंद किया जाये। अब ऐसे समय में अमेरिका ने दो 2 हफ्ते का युद्ध विराम घोषित कर पाकिस्तान को इसका क्रेडिट दे दिया। वहीं इजरायल अब भी युद्ध छेड़ हुए हैं जिससे ईरान ने होर्मूज को फिर से बंद करना

पड़ा है। यानी ऊर्जा संकट फिर से खड़ा हुआ। अब पाकिस्तान की रणनीति कहां गई हालांकि पाकिस्तान में बातचीत के लिए मेज सजाई जा रही है। लेकिन चीन जैसे चाहता है वैसे शतरंज के प्यादे की तरह पाकिस्तान को चला रहा है। पाकिस्तान को पूरी तरह मोहरा कहना सही नहीं होगा, लेकिन यह भी सच है कि उसकी विदेश नीति अक्सर आर्थिक और सैन्य निर्भरता से प्रभावित होती है। अमेरिका के साथ उसका इतिहास रहा है वहीं, चीन के साथ उसका गहरा रणनीतिक रिश्ता है । इसलिए, पाकिस्तान कई बार संतुलन बनाने वाला खिलाड़ी बन जाता है, न कि केवल मोहरा।

अगर गौर किया जाये कि चीन का असली हित क्या है ?तो इससे चीन पूरे समीकरण में ज्यादा बड़ा और दीर्घकालिक खिलाड़ी है। ईरान उसके लिए ऊर्जा (तेल-गैस) का अहम स्रोत है।उसकी बेल्ट एंड रोड रणनीति का हिस्सा है। चीन नहीं चाहता कि अमेरिका मध्य-पूर्व में पूरी तरह हावी हो। इसलिए चीन सीधे युद्ध में कूदे बिना बैकग्राउंड स्ट्रेटेजी से अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। तो क्या चीन पर्दे के पीछे है?चीन आमतौर पर खुलकर सैन्य हस्तक्षेप से बचता है आर्थिक, कूटनीतिक और अप्रत्यक्ष समर्थन देता है। इसलिए, यह कहना कि असली किरदार चीन है कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन वह पर्दे के पीछे रहकर खेलता है, न कि खुले युद्ध में।अगर अमेरिका और ईरान में बड़ा टकराव होता है तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा कि वह किसी एक पक्ष के करीब जाए। चीन इस स्थिति का इस्तेमाल अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कर सकता है। पूरे एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकता है। कहने का आशय है कि पाकिस्तान को केवल मोहरा कहना सरलीकरण होगा। वह एक मिड-लेवल स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, जो अपनी मजबूरियों और हितों के बीच संतुलन बनाता है। वहीं चीन एक बड़ा खिलाड़ी है, जो सीधे नहीं बल्कि रणनीतिक तरीके से पूरे खेल को प्रभावित करता है।

अब प्रश्न उठता है कि चीन सीधे मध्यस्थता क्यों नहीं करता?

चीन सीधे मध्यस्थता क्यों नहीं करता ? इसका कारण भी जान लें कि वैश्विक राजनीति में चीन की भूमिका लगातार बढ़ रही है, लेकिन जब बात सीधे मध्यस्थता की आती है—खासतौर पर अमेरिका- ईरान जैसे संवेदनशील विवादों में—तो चीन अक्सर परोक्ष रास्ता अपनाता है। यह सवाल महत्वपूर्ण है कि आखिर चीन खुलकर मध्यस्थता क्यों नहीं करता ?सबसे पहले लो-प्रोफाइल कूटनीति की रणनीति। चीन पारंपरिक रूप से शांत शक्ति में विश्वास करता है। वह बिना शोर-शराबे के पर्दे के पीछे से बातचीत को प्रभावित करना चाहता है, ताकि असफलता की स्थिति में उसकी साख पर आंच न आए।दूसरा आर्थिक हितों की प्राथमिकता। यानी चीन का मुख्य फोकस व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा है। मध्य पूर्व से उसे बड़े पैमाने पर तेल मिलता है। खुलकर किसी एक पक्ष की मध्यस्थता करने से उसके व्यापारिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं, खासकर सऊदी अरब और ईरान दोनों के साथ।तीसरा नॉन-इंटरफेरेंस नीति अपनाना। चीन की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत है—दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। सीधे मध्यस्थता करना कई बार इस सिद्धांत के खिलाफ माना जाता है, इसलिए वह सावधानी बरतता है।चौथी अमेरिका से टकराव से बचाव। अमेरिका अब भी वैश्विक राजनीति में प्रमुख शक्ति है। चीन खुलकर मध्यस्थता करेगा तो इसे रणनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है, जिससे दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव और बढ़ सकता है।पांचवा सही समय का इंतजार। चीन अक्सर तब सामने आता है जब उसे सफलता की संभावना ज्यादा दिखती है—जैसे ईरान-सऊदी समझौता 2023। इससे वह सफल मध्यस्थ की छवि बनाता है।चीन की चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति है। वह सीधे मंच पर आने के बजाय पर्दे के पीछे से प्रभाव डालकर अपने हितों को सुरक्षित रखना चाहता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन मध्यस्थ कम और संतुलन साधने वाला खिलाड़ी ज्यादा है।

हार-जीत नहीं है संघर्षविराम

राज कुमार सिंह

खुद को विश्व शांति और स्थिरता का ठेकेदार समझने वालों को संघर्षविराम की जरूरत समझने में 40 दिन लग गए। इस अवधि में दिखाई पड़े तबाही के मंजरों के मद्देनजर कोई भी समझदार व्यक्ति संघर्ष विराम का स्वागत ही करेगा लेकिन फिर भी यह सवाल अनुत्तरित है कि आखिर इस युद्ध से हासिल क्या हुआ? 15 दिनों के लिए घोषित संघर्ष विराम के बीच अमरीका और ईरान के प्रतिनिधि पाकिस्तान में उन शर्तों पर बातचीत करेंगे, जिन पर सहमति के बाद इस युद्ध का अंत हो जाएगा। पहले भी 26 फरवरी को जेनेवा में हुई बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति बन गई थी लेकिन वार्ता के अगले दौर से पहले ही ईरान पर हमले शुरू हो गए। जाहिर है, ईरान की ओर से भी जवाबी हमले होने ही थे। परिणामस्वरूप न सिर्फ ये 3 देश, बल्कि खाड़ी के सभी देश जंग के बीच तबाही झेलते रहे, जिसकी मार ऊर्जा संकट और महंगाई के रूप में शेष विश्व को भी झेलनी पड़ी। समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि अगर संबंधित पक्षों ने पहले ही संघर्ष की बजाय संवाद के जरिए समाधान खोजा होता तो इस तबाही से बचा जा सकता था। युद्ध के बीच अपनी-अपनी जीत के दावे करते हुए भी ईरान और अमरीका का अचानक संघर्ष विराम पर सहमत हो जाना बताता है कि जमीनी हकीकत क्या रही होगी। अपने दूसरे राष्ट्रपति काल के पहले ही साल में 8 संघर्षविराम करवाने का दावा करते हुए शांति का नोबेल मांगने वाले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इन 40 दिनों में 'बर्बादी के बादशाह' ज्यादा नजर आए। सत्ता परिवर्तन के घोषित उद्देश्य के साथ किसी दूसरे देश पर हमले कम-से-कम लोकतांत्रिक सोच तो नहीं मानी जा सकती लेकिन विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र माने जाने वाले अमरीका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने ऐसा कर दिखाया। तर्क दिया जा सकता है कि जो व्यक्ति सेना भेज कर वेनेजुएला से उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सपत्नीक उठवा चुका हो, उसके लोकतांत्रिक होने की गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। तर्क निराधार नहीं है, पर सच यह भी है कि अगर वेनेजुएला प्रकरण में अन्य देशों ने अपनी वैश्विक जिम्मेदारी का अहसास करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया की होती तो शायद पश्चिम एशिया को 40 दिन की यह युद्ध विभीषिका नहीं झेलनी पड़ती, जिसकी तपिश दूरदराज के देशों ने भी महसूस की। दरअसल दूसरे राष्ट्रपति काल की शुरुआत से ही ट्रम्प प्रवासियों और टैरिफ जैसे मुद्दों पर वैश्विक व्यवस्था को ही चुनौती देते नजर आ रहे हैं लेकिन ज्यादातर देश अपने-अपने हितों से संचालित होकर खेलते रहे। लंबे खिंचते युद्ध से तबाही और उसकी तपिश महसूस कर इस बार अमरीका के उन परंपरागत मित्र देशों ने भी उसका साथ देने से इंकार कर दिया, जिन्हें ट्रम्प अपने साथ ही मान कर चलते रहे। अमरीका के साम्राज्यवादी और भोगवादी चरित्र के बावजूद वहां के नागरिकों ने भी सड़कों पर उतर कर ट्रम्प के इस युद्धोन्माद का विरोध करने का साहस दिखाया। इसी साल होने वाले मध्यावधि चुनावों के मद्देनजर विरोधी डैमोक्रेट्स को कारगर मुद्दा मिल गया, तो रिपब्लिकन्स भी अपने राष्ट्रपति की हरकतों के राजनीतिक खतरे महसूस करने लगे। कहना नहीं होगा कि इन चौतरफा दबावों के बीच संघर्ष की राह तलाशते हुए भी ट्रम्प अपने अहंकारी कारोबारी चरित्र से बाज नहीं आए। सप्ताहांत में युद्ध समाप्ति की भविष्यवाणी से बाजार में गिरावट तथा फिर सप्ताह के शुरू में युद्धोन्माद और भड़का कर ट्रम्प द्वारा अपने करीबियों को शेयर बाजार से मुनाफा कमाने के किस्से अमरीकी मीडिया में आम हैं। कभी ट्रम्प स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से अमरीका को बेपरवाह बता कर अन्य देशों पर उसे खुलवाने के लिए दबाव बनाते दिखे, तो कभी 48 घंटे में उसे न खोलने पर ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी देते। कभी चार दिन का अल्टीमेटम देकर उसे 10 दिन तक बढ़ा दिया, तो फिर ईरानी सभ्यता की ही समाप्ति के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। जाहिर है, किसी जिम्मेदार लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति से ऐसा आचरण अपेक्षित नहीं लेकिन यही हमारे समय का सच है। अनेक बार हमले के लक्ष्य हासिल कर लेने और ईरान का सैन्य ही नहीं, शासकीय ढांचा भी नष्ट करने के दावे करने वाले ट्रम्प अगर अब 40 दिनों बाद 15 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमत हो गए तो उसकी सफलता को ले कर आश्वस्त होना आसान नहीं।

सत्ता के सवाल पर भाजपा में असमंजस

अभिलाष श्रीवास्तव

मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिए कटे लाखों नामों पर होने वाले विवाद के बावजूद भाजपा को अबकी बंगाल की सत्ता पर काबिज होने का भरोसा है। उसके संकल्प पत्र में भी यही भरोसा झलकता है। लेकिन उसके बड़े-बड़े दावों के बावजूद नेताओं के निजी बातचीत में इस सवाल पर पार्टी में असमंजस का संकेत मिलता है।

पार्टी ने पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए इस बार राज्य की तमाम 294 सीटों के लिए अलग-अलग रणनीति तैयार की है। शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम के अलावा ममता के गढ़ भवानीपुर में उतारना और आर.जी. कर कांड की पीड़िता की मां को पानीहाटी सीट पर टिकट देना उसकी इसी रणनीति का हिस्सा है।

भवानीपुर में शुभेंदु के मैदान में उतारने का एकमात्र मकसद ममता पर मानसिक दबाव बना कर उनको इसी इलाके में फंसाए रखना है ताकि वो राज्य के दूसरे इलाकों में चुनाव प्रचार पर ज्यादा समय नहीं दे सकें।

पहले चरण में जिन 152 सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर बंगाल के वो इलाके भी शामिल हैं जहां पार्टी पारंपरिक तौर पर मजबूत रही है। लेकिन बावजूद इसके वो वहां अतिरिक्त आत्मविश्वास का शिकार होने से बच रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि हम तमाम सीटों पर कांटे की टक्कर मान कर आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव से पहले करीब छह महीने तक केंद्रीय नेताओं के साथ चले मंथन के बाद हर सीट के लिए अलग रणनीति तैयार की गई है।

दक्षिण बंगाल में खासकर कोलकाता और उससे सटे इलाके तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहे हैं। लेकिन भाजपा ने इस बार यहां भी सेंध लगाने की रणनीति तैयार की है। उसे उम्मीद है कि इस बार घुसपैठ और भ्रष्टाचार के पारंपरिक मुद्दों के अलावा प्रतिष्ठान विरोधी लहर का भी फायदा मिलेगा।

दक्षिण 24-परगना में आम लोग भी इस बार बदलाव के पक्ष में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि एक बार भाजपा को भी मौका देना चाहिए। हालांकि लोग इस पुरानी कहावत की भी याद दिलाते हैं कि जे जाय लंका सोई होए रावन यानी जो लंका जाता है वह रावण हो जाता है। बावजूद इसके कुछ इलाकों में भाजपा पिछली बार के मुकाबले मजबूत नजर आती है। पहले जिन इलाकों में

उसका कोई नामलेवा तक नहीं था वहां भी उसके झंडे और पोस्टर नजर आने लगे हैं।

तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को भी इस खतरे का अंदाजा है, इसलिए वो अपनी तमाम रैलियो में लोगों से भाजपा को एक भी वोट नहीं देने की अपील कर रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पार्टी इस बार उन करीब पांच दर्जन सीटों पर खास ध्यान दे रही है जहां पिछली बार हार-जीत का अंतर कम था। वर्ष 2018 के लोकसभा चुनाव से उसकी स्थिति लगातार मजबूत होने की एक वजह वाममोर्चे के ज्यादातर वोट उसके पक्ष में जाना है। उस साल पार्टी के मिलने वाले वोट 17 फीसदी बढ़े थे। उसे इस बार भी वाममोर्चा के तृणमूल कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाने की उम्मीद है। भाजपा नेताओं के मुताबिक, हुमायूं कबीर और ओवैसी के अलावा सीपीएम और वाममोर्चा तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध लगाएंगे। इसकी वजह से पार्टी को कई अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं। पार्टी का अंदरूनी हिसाब 125 से 150 सीटों का है।

लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि पूरा जोर लगाने के बावजूद वह अधिकतम सौ सीटों तक पहुंच सकती है। इसकी वजह कई इलाकों में उसके संगठन का कमजोर होना है। लेकिन उसके साथ इस बार चुनाव आयोग की सक्रियता और भारी तादाद में सुरक्षाबलों की तैनाती से ग्रामीण इलाकों में चुनावी धांधली पर अंकुश लग सकता है। इससे तृणमूल को नुकसान होगा और उसका नुकसान पार्टी के लिए फायदे का सौदा बन सकता है।

दक्षिण बंगाल में मेदिनीपुर इलाके में अधिकारी परिवार के कारण पार्टी की स्थिति मजबूत है। इसके अलावा बीरभूम, मुर्शिदाबाद और मालदा में वह कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की उम्मीद कर रही है। देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक बहुल जिले मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में पिछली बार उसे दो सीट मिली थी, बाकी तृणमूल कांग्रेस को मिली थी। हुमायूं कबीर के मैदान में होने की वजह से पार्टी को अबकी वहां कम से कम पांच सीटें जीतने की उम्मीद है।

दूसरी ओर, वाममोर्चा इस बार कांग्रेस का साथ छोड़ कर अकेले मैदान में उतरी है। उसने अपने पैरों तले खिसकती जमीन पर अंकुश लगाने के लिए बेदाग छवि वाले नए चेहरों पर भरोसा जताया है। उम्मीदवारों की सूची में 27 महिलाओं के अलावा दर्जनों ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है। इनको टिकट देने का मकसद राज्य के युवा वोटरों को आकर्षित करना है। सीपीएम ने जिन युवाओं को मैदान में उतारा है उनमें से कई लोग आरजी कर कांड के खिलाफ लंबे समय तक आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे हैं। मोर्चा का दावा है कि इस बार उसने तृणमूल और भाजपा से असंतुष्ट वोटरों के सामने एक नया विकल्प पेश किया है। वर्ष 2011 में तृणमूल कांग्रेस से हारने के बावजूद पार्टी ने इस लाल किले में करीब 40 फीसदी वोटों पर कब्जा बरकरार रखा था। लेकिन अगले दस साल में यह आंकड़ा घटकर पांच फीसदी से नीचे पहुंच गया। इसी वजह से वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में उसका खाता तक नहीं खुल सका। वैसे, वोटों में गिरावट का यह सिलसिला काफी पहले ही शुरू हो गया था।

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीएम और उसके सहयोगी दलों को महज 6.28 फीसदी वोट और दो सीटें मिली थी। दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे थे। तब भाजपा का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था और वह दो से 18 सीटों तक पहुंच गई थी। यही वजह है कि 2019 में भाजपा को मिले वोटों का आंकड़ा 23 फीसदी बढ़ कर 40.6 फीसदी तक पहुंच गया। वाममोर्चा के कई नेता मानते हैं कि वामपंथी दल अपने समर्थकों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहे हैं। ज्यादातर नेता 34 साल तक सत्ता में रहने की खुमारी से मुक्त नहीं हो सके हैं। लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण पार्टी और प्रशासन के बीच की विभाजन रेखा धूमिल हो गई थी। विपक्ष से खास चुनौती नहीं मिलने की वजह से खासकर सीपीएम सर्वशक्तिमान होकर उभरी और पार्टी में भ्रष्टाचार भी जड़ें जमाने लगा। ज्यादातर सरकारी काम पार्टी दफ्तर से ही होने लगे थे। यह कहना ज्यादा सही होगा कि सीपीएम के दफ्तर समानांतर प्रशासन का केंद्र बन गए थे। लेकिन पुरानी गलतियों को भुला कर पार्टी इस बार अपने बूते बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है।

खालसा पंथ की स्थापना और फसलों की कटाई की खुशी का पर्व है बैसाखी

सुखबीर सिंह

बैसाखी का पावन पर्व सिख इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने सन 1699 में आनंदपुर साहिब की पावन धरती पर खालसा पंथ की स्थापना की थी, उस समय उनका नाम गोबिंद राय था। यह स्थापना किसी साधारण धार्मिक आयोजन का परिणाम नहीं थी बल्कि उस समय के सामाजिक अन्याय, धार्मिक अत्याचार और मानवाधिकारों के हनन के विरुद्ध एक क्रांतिकारी कदम था ।

उस समय समाज में भय, भेदभाव और जबरन धर्म परिवर्तन जैसी समस्याएं बढ़ रही थीं, आम जनमानस में साहस और आत्मसम्मान की कमी हो रही थी । ऐसे समय में गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ऐसे पंथ की स्थापना की जो न केवल आध्यात्मिक रूप से जागरूक हो बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस भी रखे । खालसा पंथ का मूल उद्देश्य था संत सिपाही् तैयार करना जो भक्ति और शक्ति दोनों का संतुलन बनाए रखे।

बैसाखी के ऐतिहासिक दिवस पर गुरु गोबिंद राय जी ने विशाल सभा में आव्हान किया कि जो देश धर्म के लिए अपने प्राणों का त्याग कर सकता है वो सामने आए । सभा में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया फिर पीछे से एक व्यक्ति उठा और सहजता से चलते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी के पास आया और बोला कि मैं अपने प्राणों का बलिदान देने को तैयार हूं गुरु गोविंद सिंह जो उस समय गोविंद राय कहलाते थे उन्हें अंदर ले गए और पंडाल के पीछे से तलवार चलने की जोरदार आवाज आई और खून की धार सभा की तरफ बहने लगी, गुरुजी बाहर आए उनके हाथों में रक्त रंजित तलवार थी उन्होंने दोबारा आवाज लगाकर पूछा कि और कौन गुरु का प्यारा देश और धर्म के लिए जान दे सकता है फिर एक व्यक्ति उठा और उसने भी देश धर्म के लिए अपने प्राण कुर्बान करने की बात कही गुरुजी उससे भी अंदर ले गए फिर जोरदार आवाज और खून की धार, इस तरह एक.एक कर पांच लोगों को गुरु जी पंडाल के पीछे ले गए और खून की धार बाहर बहती रही पूरी सभा में सन्नाटा था लोग आश्चर्य में थे कि गुरु जी ने यह क्या किया ? क्यों किया ? यह परीक्षा केवल आस्था की नहीं बल्कि समर्पण, साहस और विश्वास की थी । जब पाँच सिख इस परीक्षा में खरे उतरे तब गुरु जी ने उन्हें अमृत पान करवाकर

खालसा बनाया ।

गुरु जी ने जिन्हें अमृत पान करवाकर पंज प्यारे सजाया उनमें भाई दया सिंह जी (लाहौर के निवासी) - भाई धरम सिंह जी (हस्तिनापुर/मेरठ के निवासी) - भाई हिम्मत सिंह जी (जगन्नाथ पुरी के निवासी) - भाई मोहकम सिंह जी (द्वारका के निवासी) - भाई साहिब सिंह जी (बीदर के निवासी) थे । इसके पश्चात जो घटना घटी वही सिक्ख परंपरा की सबसे अद्वितीय और प्रेरणादायक मिसाल बनी। गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं उन्हीं पाँच प्यारों से अमृत ग्रहण किया और स्वयं को भी खालसा में शामिल किया। उसके बाद से गुरु गोविंद राय का नाम गुरु गोबिंद सिंह पड़ा ।

यही वह ऐतिहासिक क्षण है, जिसके कारण सिख परंपरा में कहा जाता है, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला।

इस पंक्ति का गहरा अर्थ है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु और शिष्य के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया। उन्होंने यह संदेश दिया कि सच्चा गुरु वही है जो स्वयं भी उसी अनुशासन मर्यादा और नियमों का पालन करे, जो वह अपने अनुयायियों को सिखाता है। उन्होंने स्वयं को ऊँचा नहीं रखा बल्कि अपने अनुयायियों के साथ समान स्तर पर खड़ा किया। यह समानताए विनम्रता और नेतृत्व का सर्वोच्च उदाहरण है। इससे यह सिद्ध होता है कि सिक्ख पंथ में किसी भी प्रकार का ऊँच.नीच या भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। आज भी गुरुद्वारों में गरीब . अमीर सब एक साथ एक लाइन में बैठकर लंगर ग्रहण करते हैं। आज के समय में जब समाज अनेक चुनौतियों से गुजर रहा हैकृनैतिक मूल्यों में गिरावट, आपसी विभाजन और युवाओं का भटकावकृतब गुरु गोबिंद सिंह जी का यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। हमें यह सीख मिलती है कि नेतृत्व केवल आदेश देने का नहीं बल्कि स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करने का नाम है।

छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर सिक्ख समाज सदैव सरबत दा भला की भावना के साथ सेवा, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता आया है। आज बैसाखी के इस पावन अवसर पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम गुरु साहिब के दिखाए मार्ग पर चलते हुए समाज में न्याय, समानता और सेवा की भावना को और सुदृढ़ करें। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हउ करौं निवासश्

यह वचन हमें याद दिलाता है कि खालसा केवल एक पहचान नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। आस्था, साहस और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश।

बैसाखी का पावन पर्व सिक्ख समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अवसर है। यह केवल फसल कटाई का उत्सव नहीं बल्कि धर्म, साहस, समानता और सेवा के मूल्यों को आत्मसात करने का दिन भी है । आज के बदलते सामाजिक और वैश्विक परिदृश्य में बैसाखी हमें अपने मूल सिद्धांतों की ओर लौटने और उन्हें व्यवहार में उतारने का संदेश देती है। बैसाखी का दिन हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब गुरु साहिब ने समाज में व्याप्त अन्याय, भेदभाव और भय को समाप्त करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

हम बैसाखी के संदेश को केवल उत्सव तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। धर्म का पालन केवल पूजा.पाठ तक सीमित न रहकर सत्य, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलना है। सेवा ;सेवा भावद्ध के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता करना ही सच्ची श्रद्धा है। समानता और भाईचारा आज के समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जहाँ जाति, धर्म और वर्ग के भेद को समाप्त करना हमारा कर्तव्य है। छत्तीसगढ़ की धरती पर सिक्ख समाज हमेशा से सेवा, सद्भाव और भाई चारे का प्रतीक रहा है। चाहे प्राकृतिक आपदाएं हों या सामाजिक संकट, सिक्ख समाज ने सरबत दा भला के सिद्धांत पर चलते हुए हर जरूरतमंद की सहायता की है। आज भी हमें यही संकल्प लेना होगा कि हम अपने आसपास के समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे।

तमिलनाडु में क्या गेम चेंजर बनेंगे थलापति

महेंद्र बाबू कुरुवा

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 234 सीटों के लिए 'चतुष्कोणीय' मुकाबला देखने को मिलेगा। सत्ताधारी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (द्रमुक) अपने 'धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन', जिसमें कांग्रेस समेत 23 पार्टियां शामिल हैं, के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर, अन्नाद्रमुक राजग के तहत भाजपा के साथ सत्ता-विरोधी रुझान का लाभ उठाकर बदलाव के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इसके साथ ही, सीमन के नेतृत्व वाली नाम तमिलर काची (एनटीके) भी कड़ी टक्कर दे रही है, पर सबकी नजरें चौथे खिलाड़ी अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय चंद्रशेखर पर टिकी हैं, जिन्हें 'थलापति' विजय कहा जाता है। विजय ने अपनी पार्टी टीवीके के साथ तमिल राजनीति में अचानक प्रवेश किया है। व्यापक लोकप्रियता के कारण उन्हें संभावित 'गेम चेंजर' माना जा रहा है, खासकर ऐसे राज्य में, जहां करीब छह दशकों से द्रविड़ दलों ने शासन किया है और राष्ट्रीय दलों को मौका नहीं दिया। फिलहाल, विजय की टीवीके अकेले सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विजय खुद को मौजूदा द्रविड़ पार्टियों के विकल्प के रूप में पेश करते हैं, पर लगता है, वह भी द्रविड़ राजनीति के मूल सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। विजय राज्य की राजनीति पर कितना असर डाल पाएंगे, यह जानने के लिए उस 'द्रविड़' राजनीति के मॉडल को समझना जरूरी है, जो करीब 100 वर्षों से तमिल राजनीतिक विमर्श का अभिन्न अंग रहा है। द्रविड़ राजनीति की शुरुआत ईवी रामास्वामी नायकर से हुई थी, जिन्हें 'पेरियार' के नाम से जाना जाता है। उन्होंने हाशिये पर पड़े समुदायों और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई, धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मजबूत तमिल सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा दिया। 1943 में पेरियार ने जिस द्रविड़ पार्टी की स्थापना की, वह बाद में दो पार्टियों-द्रमुक और अन्नाद्रमुक में बंट गई। तर्कवाद और आत्म-सम्मान के दर्शन पर बनी इन पार्टियों का नेतृत्व भी फिल्मी हस्तियों ने ही किया, जिन्हें मतदाताओं ने भी स्वीकार किया। यह तमिल राजनीति का ऐसा अनोखा विरोधाभास है, जो तर्क-वितर्क से परे है। इसी विरोधाभास ने विजय को राजनीति में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। विजय की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह उस खाई को भरने में कहां तक कामयाब होते हैं, जो दोनों द्रविड़ दलों ने पिछले साठ वर्षों में बनाई है, और जनता उसे किस नजरिये से देखती है। तमिलनाडु में शासन करने वाली दोनों पार्टियों ने जिस बात को नजरअंदाज किया, वह है समावेशिता और सामाजिक न्याय का मुद्दा-जो 1940 के दशक में द्रविड़ आंदोलन के केंद्र में था। दोनों पार्टियों के शासनकाल में पिछड़े वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा है, पर कई ऐसी प्रभावशाली जातियां हैं, जिन्हें ओबीसी की श्रेणी में रखा गया, और चुनावी नतीजों पर आज भी उनकी मजबूत पकड़ बनी हुई है। महिलाएं और दलित इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। गृह मंत्रालय द्वारा 2022 में जारी आंकड़ों में तमिलनाडु के 38 में से 37 जिलों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों पर अत्याचार के मामले में 'संवेदनशील' घोषित किया गया। दूसरा पहलू, जिससे लोगों का मोहभंग हुआ, वह है इन पार्टियों के राजनीति करने का तरीका। द्रमुक और अन्नाद्रमुक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं, पर उनके राजनीति करने का तरीका और बयानबाजी एक जैसी है। दोनों ही पार्टियां राज्य की समस्याओं के लिए हिंदी या केंद्र सरकार को दोषी ठहराती हैं। फिर भी, राष्ट्रीय पार्टियों ने द्रविड़ पार्टियों द्वारा पैदा शून्य को भरने और उनके शासन से उपजे असंतोष का राजनीतिक लाभ उठाने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की। कांग्रेस और भाजपा, दोनों ने ही क्रमशः द्रमुक या अन्नाद्रमुक के कनिष्ठ साझेदार तक खुद को सीमित रखा। भाजपा ने इस घेरे को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर उसे सीमित सफलता ही मिली, क्योंकि उसे अपना नेतृत्व उन्हीं लोगों में से चुनना पड़ा, जो द्रविड़ दलों की छत्रछाया में पले-बढ़े थे। तमिलनाडु अकेला ऐसा राज्य है, जहां अनुकूल धार्मिक जनसांख्यिकी के बावजूद भाजपा सीमांत खिलाड़ी बनी हुई है।

मन की साधना

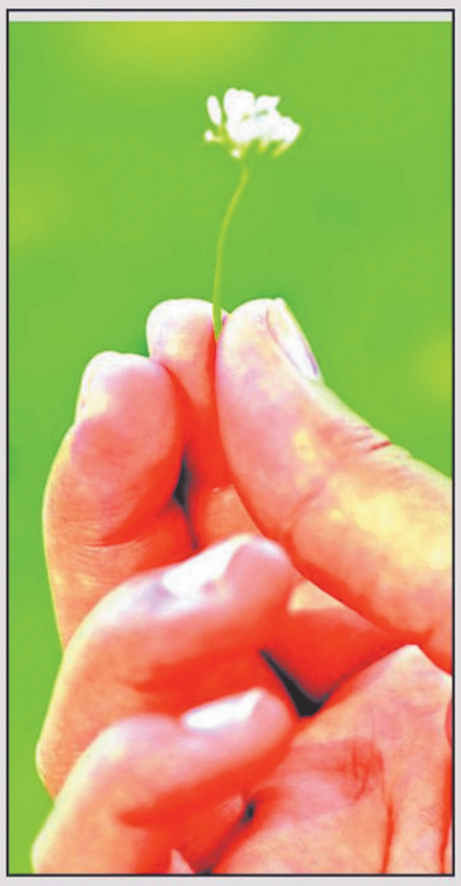

चतुर्मास का समय निकट आया तो भिक्षु सुशांत ने बुद्ध से आग्रह किया प्रभु, मैं नगरवधू सोमलता के सान्निध्य में अपना चतुर्मास व्यतीत करना चाहता हूं। कृपया इसकी आज्ञा प्रदान करें। यह सुनकर बुद्ध मुस्कराए। वह समझ गए कि यह वहां जाकर मन को साधकर सच्चा साधक होना चाहता है, लेकिन अन्य भिक्षुओं ने इस पर आपत्ति जताई। उन्हें संदेह था कि सुशांत कहीं अपने पथ से विचलित न हो जाए, पर बुद्ध ने भिक्षुओं के विरोध के बावजूद उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ और आगे बढ़कर आना। सुशांत सोमलता के पास पहुंचा। वहां सब उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन सुशांत अपने संकल्प पर अडिग था।

इधर सोमलता के घुंघरुओं की आवाज गूंजती और उधर सुशांत अपनी साधना में लीन रहता। सोमलता सुशांत को रिझाने का प्रयास करती, मगर वह निर्लिप्त रहता। एक मास गुजर गया मगर सोमलता सुशांत को डिगा न सकी। हां, उससे थोड़ी सहानुभूति अवश्य होने लगी। उसने दूसरों को भी साधना के क्षणों में शांत रहने को कह दिया। चौथा मास आते-आते सुशांत ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया था। वह सोमलता या अन्य सुंदरियों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता था। संगीत उसे बुद्ध-वाणी की तरह लगता था और नृत्यालय देवालय की तरह। चार मास पूर्ण हुए और सुशांत अपने मठ की ओर वापस चला तो सबने आश्चर्य से देखा- भिक्षुणी बनी सोमलता उसके पीछे-पीछे अपना सर्वस्व त्याग कर जा रही थी। सोमलता अपने रूप-रंग से सुशांत को रिझा न सकी, मगर सुशांत के तप का प्रभाव सोमलता पर दिख रहा था। सुशांत वास्तव में आगे बढ़ गया था।

भाग्य और पुरुषार्थ

राजा विक्रमादित्य के दरबार में कई ज्योतिषी थे। मगर वह कोई काम शुभ लग्न देख कर या ज्योतिषी की सलाह लेकर नहीं करते थे। एक दिन राज ज्योतिषी उनके पास आए और बोले, महाराज, आप के दरबार में कई ज्योतिषी हैं। आप की तरफ से उन्हें सभी सुविधाएं मिली हुई हैं, पर आप कभी हमारी सेवाएं नहीं लेते। आज मैं आप की हस्तरेखा देख कर यह जानना चाहता हूं कि आप ऐसा क्यों करते हैं?

राजा ने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं आप लोगों से सलाह ले सकूं। जहां तक हस्तरेखा की बात है तो मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। लेकिन आप कह रहे हैं तो देख लीजिए। हाथ देख कर राज ज्योतिषी चक्कर में पड़ गए। उनकी आवाज बंद हो गई। राजा ने पूछा, क्या हुआ। आप इतने परेशान क्यों हैं? राज ज्योतिषी ने कहा, राजन्, आप की हस्तरेखाएं तो कुछ और कहती हैं। ज्योतिष के अनुसार आप को तो दुर्बल और दीनहीन होना चाहिए था। लेकिन आप तो इसके विपरीत हैं। हजारों साल से ज्योतिष विद्या पर विश्वास करने वाले लोग आपकी रेखाएं देख कर भ्रमित हो जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा कि ज्योतिष को सच मानूं या आप की रेखाओं को। विक्रमादित्य ने कहा, अभी तो आप ने मेरे बाहरी लक्षणों को ही देखा है, अब आप हमारे अंदर झांक कर देखिए। इतना कह कर राजा ने तलवार की नोक अपने सीने में लगा दी। राज ज्योतिषी घबरा कर बोले, बस महाराज, रहने दीजिए।

राजा ने कहा- ज्योतिषी महाराज, आप परेशान मत हों। ज्योतिष विद्या भी तभी सार्थक सिद्ध होती है, जब मनुष्य में कुछ करने का संकल्प हो। हस्तरेखाएं तो भाग्य नहीं बदल सकतीं, लेकिन मनुष्य में यदि पुरुषार्थ है, अभाग्य से लड़ने की शक्ति है तो उसकी नकारात्मक रेखाएं भी अपने रूप बदल सकती हैं। लगता है मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। राज ज्योतिषी अवाक हो गए।

गीता में है जीवन का ज्ञान

गीता डॉक्टर की भांति है। बस फर्क इतना ही है कि डॉक्टर शरीर के रोगों का इलाज करता है, जबकि गीता मन के रोगों का इलाज करती है और उन्हें दूर करने का मार्ग दिखाती है।

गीता का उपदेश जीवन की धारा है। चूंकि गीता में जीवन की सच्चाई छिपी है और इसमें जीवन में आने वाली दुश्वारियों के कारण व निवारण दोनों को ही विस्तार से समझाया गया है। इसलिए गीता के उपदेश विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और हर वर्ग को प्रभावित करते हैं।

गीता डॉक्टर की भांति है। बस फर्क इतना ही है कि डॉक्टर शरीर के रोगों का इलाज करता है, जबकि गीता मन के रोगों का इलाज करती है और उन्हें दूर करने का मार्ग दिखाती है। जिस प्रकार डॉक्टर रोगी को रोग के निवारण के साथ-साथ उसके कारण भी बताता है। ठीक उसी प्रकार से गीता का अगर गहनता से अध्ययन किया जाए तो इससे मन के रोगों का कारण और निवारण दोनों का पता चल जाता है। गीता मन के रोगों को दूर करने का एक सशक्त माध्यम है।

गीता ज्ञान से मानव जीवन में मोह को भी आसानी से दूर किया जा सकता है। मोह जीवन लीला को धीरे-धीरे नष्ट कर देता है। जीवन में दुखों का सबसे बड़ा कारण मोह ही है। जीवन को अगर सफल बनाना है और मोह से मुक्ति पानी है तो गीता की शरण में जाना पड़ेगा। गीता से ज्ञान पा कर मानव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। गीता का ज्ञान मनुष्य को उसकी आत्मा के अमर होने के विषय में बोध करवा कर अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण निष्ठा से करने को प्रेरित करता है। परमात्मा ने मनुष्य को देह केवल भोग के लिए प्रदान नहीं की है, अपितु हमें इसका उपयोग मोक्ष प्राप्ति के लिए करना चाहिए।

साधू व नदी कभी एक स्थान पर नहीं रुकते और निरंतर आगे बढ़ते हुए विभिन्न स्थानों पर जन-जन के हृदयों में अपने ज्ञान व भक्ति के प्रभाव से उन्हें लाभांवित व आनंदित करते हैं। प्रत्येक मानव को पूरी श्रद्धा व निष्ठा से पर-उपकार के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने ज्ञान से जगत को प्रकाश मान करने का प्रयास करते रहना चाहिए, असल में यही मानव धर्म है।

अगर श्रीमद्भगवद् गीता का अध्ययन नित्य करें, तो इस बात का आभास सहजता से होता है कि उसमें सिखाया कुछ नहीं गया है, बल्कि समझाया गया कि इस संसार का स्वरूप क्या है? उसमें यह कहीं नहीं कहा गया कि आप इस तरह चलें या उस तरह चलें, बल्कि यह बताया गया है कि किस तरह की चाल से आप किस तरह की छवि बनाएंगे? उसे पढ़कर मनुष्य कोई नया भाव नहीं सीखता, बल्कि संपूर्ण जीवन सहजता से व्यतीत करने के मार्ग पर चल पड़ता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें एक वैज्ञानिक सूत्र है कि 'गुण ही गुणों को बरतते हैं।' इसका मतलब यह है कि जैसे संकल्पों, विचारों तथा कर्मों से आदमी बंधा है, वैसा ही वह व्यवहार करेगा। उस पर खाने-पीने और रहने के कारण अच्छे तथा बुरे प्रभाव होंगे। सीधी बात यह है कि अगर आप यह चाहते हैं कि अपने ज्ञान के आईने में आप स्वयं को अच्छे लगें तो अपने संकल्प, विचारों तथा कर्मों में स्वच्छता के साथ अपनी खान-पान की आदतों तथा रहन-सहन के स्थान का चयन करना पड़ेगा।

अगर आप आने अंदर दोष देखते हैं तो विचलित होने की बजाय यह जानने का प्रयास करें कि आखिर वह किसी बुरे पदार्थ के ग्रहण करने या किसी व्यक्ति की संगत के परिणाम से आया है। जैसे ही आप गीता का अध्ययन करेंगे, आपको अपने अंदर भी ढेर सारे दोष दिखाई देंगे और उन्हें दूर करने का मार्ग भी पता लगेगा।

गीता किसी को प्रेम करना, अहिंसा में लिप्त होना नहीं सिखाती, बल्कि प्रेम और अहिंसा का भाव अंदर कैसे पैदा हो, यह समझाती है। सिखाने से प्रेम या अहिंसा का भाव नहीं पैदा होगा, बल्कि वैसे तत्वों से संपर्क रखकर ही ऐसा करना संभव है। कोई दूसरे को प्रेम नहीं सिखा सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति का घृणा पैदा करने वाले तत्वों से संबंध है, उसमें प्रेम कहां से पैदा होगा?

श्रीमद्भगवद् गीता में चार प्रकार के भक्त बताए गए हैं। भगवान की भक्ति होती है तो जीव से प्रेम होता है। अतः भक्ति की तरह प्रेम करने वाले भी चार प्रकार के होते हैं-आर्ती, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। पहले बाकी तीन का प्रेम क्षणिक होता है जबकि ज्ञान का प्रेम हमेशा ही बना रहता है। अगर आपके पास तत्व ज्ञान है तो आप अपने पास प्रेम व्यक्त करने वालों की पहचान कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी आपको हांक कर ले जाएगा और धोखा देगा।

जीवन का आधार है आध्यात्मिक ऊर्जा

ऊर्जा एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, जिसे हम देख नहीं सकते, बल्कि उसका अनुभव कर सकते हैं। यही ऊर्जा हमारे जीवन का आधार है।

विज्ञान की भाषा

विज्ञान इन अदृश्य शक्तियों को एनर्जी कहता है। उदाहरण के लिए बिजली से बल्ब जलता है, पंखे चलते हैं, लेकिन हम बिजली को कभी नहीं देख पाते हैं। हम उसका न केवल कार्य, बल्कि परिणाम भी देखते हैं। उसके स्वरूप के बारे में जान पाना कठिन है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जीव में ऊर्जा मौजूद होती है, जिससे जीव में प्राण-शक्ति का संचार होता रहता है। दूसरे शब्दों में कहें, तो इस प्राण-शक्ति को हम देख नहीं पाते हैं।

संसार के सभी प्राणियों में ऊर्जा मौजूद है। वास्तव में यह ऊर्जा हमारे जीवन का आधार है। इसे हम अणु, परमाणु, एनर्जी आदि नामों से जानते हैं। यानी अपनी सुविधा के अनुसार, हम ऊर्जा को अलग-अलग नाम दे देते हैं। यह एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, जिसका हम केवल अनुभव ही कर सकते हैं, देख नहीं सकते। हम अपनी आंखों से तो पृथ्वी पर मौजूद सभी पदार्थों को देख लेते हैं, लेकिन ऊर्जा को देख पाना हमारे लिए संभव ही नहीं हो पाता है। लेकिन उन्हें महसूस जरूर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इन अदृश्य शक्तियों के अस्तित्व को अस्वीकार कर पाना हमारे लिए असंभव होता है।

ऊर्जा और अध्यात्म का संबंध

अध्यात्म की भाषा में ऊर्जा को न केवल प्राण-वायु या आत्मा कहा जाता है, बल्कि जीव को ईश्वर का अंश भी माना जाता है। यह ऊर्जा ही है, जो सभी जीवों को जिंदा रखने में मदद करता है। हम देखते हैं कि अदृश्य शक्ति, यानी ऊर्जा के सहारे हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। जैसे ही वह अदृश्य-शक्ति की लोप होती है, हमारे शरीर की सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। शरीर के सभी अंग-आंख, नाक, कान, यहां तक कि इंद्रियां भी काम करना बंद कर देती हैं और शरीर निष्क्रिय हो जाता है।

हम यह सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर वह कौन सी शक्ति है, जो हमारे अंगों को संचालित करती है? आज का विज्ञान भले ही चांद, तारों और ग्रहों के बारे में हमें जानकारी देता हो, लेकिन आज भी इस अदृश्य-शक्ति को समझने की क्षमता अभी तक विज्ञान के पास नहीं है। शायद इसलिए कहा जाता है कि जहां विज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है, वहीं से महा विज्ञान शुरू हो जाता है। वास्तव में यह महाविज्ञान अध्यात्म है, जीवन दर्शन है। हमारा जीवन-दर्शन न केवल जीवन के अनुभवों के बारे में बताता है, बल्कि जीवन के रहस्यों को भी समझने का प्रयास करता है। यही वजह है कि इसकी पढ़ाई विद्यालयों या महाविद्यालयों में नहीं होती है। ऋषि-मुनियों ने वर्षों पूर्व ऐसे ही रहस्यों को समझने की कोशिश की थी। यदि इस रहस्य को समझने की स्थिति में जीव आ जाता है, तो उसे जीवन-शक्ति का अनुभव भी होने लगता है।

जीवन-शक्ति का अनुभव प्राप्त करने के लिए हमे सबसे पहले ऊर्जा के अदृश्य स्वरूप का अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन-शक्ति का केवल अनुभव किया जा सकता है, देखा या परखा नहीं जा सकता है। हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनता है, लेकिन इस देखने और सुनने की प्रक्रिया को हम केवल अनुभव कर सकते हैं। यदि हम अपने अनुभवों को न केवल अपने अंतर्मन में उतार लेते हैं, बल्कि इस प्रक्रिया के आदी भी हो जाते हैं, तो इसे ही साधना कहा जाता है। यह साधना ही है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन-शक्ति का अनुभव करने लगता है। इसके लिए हमें आत्म-केंद्रित होना अति आवश्यक होता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

पवन खेड़ा केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंची असम सरकार

नई दिल्ली। असम सरकार ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यह जमानत तेलंगाना हाई कोर्ट ने उस मामले में दी थी, जो असम में उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल तेलंगाना हाईकोर्ट ने खेड़ा को एक हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट की जज न्यायमूर्ति सुजाना कलासिकम ने कहा कि पवन खेड़ा को एक हफ्ते का समय दिया जाता है ताकि वह संबंधित कोर्ट में जाकर नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकें। यह मामला असम पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। पवन खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को दावा किया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और विदेश में संपत्ति है, जिसकी जानकारी चुनावी हलफनामे में नहीं दी गई।

बिहार का अगला कप्तान कौन? भाजपा में सस्पेंस बरकरार

पटना। बिहार एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दौर में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक के बाद पद छोड़ने वाले हैं। बैठक में अब कुछ ही घंटे शेष हैं, ऐसे में सभी की निगाहें भाजपा के अगले कदम और नेतृत्व के चयन पर टिकी हैं, जो राज्य के भविष्य को आकार देगा। निवर्तमान मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को सुबह 11 बजे अपनी संभावित अंतिम मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है। इसके तुरंत बाद, उनके राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने की उम्मीद है। सत्ता हस्तांतरण की तैयारियां पहले से ही चल रही हैं और आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग की व्यवस्था की जा रही है। नीतीश कुमार ने सर्कुलर रोड स्थित 7 नंबर के अपने आधिकारिक आवास को खाली करना भी शुरू कर दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनका पद छोड़ना निकट है। एनडीए गठबंधन में प्रमुख सहयोगी रही भाजपा, जो बिहार में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनी, अब उसके पास मौका है।

जनता उन्हें जवाब देगी जो गुजरातियों को मूर्ख समझते हैं

वडोदरा। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नगर निगम चुनाव अभियान का आगाज करते हुए गृह राज्य मंत्री (उपमुख्यमंत्री स्तर के नेता) हर्ष संघवी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता का अपमान करने वालों को आने वाले चुनावों में करारा सबक मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कुछ दिन पूर्व गुजरात के लोगों को ''अशिक्षित'' कहा था और दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उन्हें ''बेवकूफ'' बना रहे हैं। संघवी ने खरगे के इस बयान के एक सप्ताह के बाद यह बात कही है। गुजरात में 34 जिला पंचायतों, 260 तालुका पंचायतों, 84 नगरपालिकाओं और 15 नगर निगमों (जिनमें अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा शामिल हैं) के लिए चुनाव 26 अप्रैल को होंगे। मतगणना 28 अप्रैल को होगी।

लालू यादव की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

नई दिल्ली। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जमीन के बदले नौकरी मामले में उनके और उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर से संबंधित कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने यादव को निचली अदालत में पेश होने से भी छूट दे दी। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई की प्राथमिकी को सोमवार को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री यादव को सुनवाई के दौरान निचली अदालत में पेश होने से छूट दे दी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह इस बात पर कोई राय नहीं दे रही है कि धारा 17ए पिछली तारीख से लागू होती है या भविष्य में।

धान बोनस नीति : केंद्र-तमिलनाडु में टकराव गहराया

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को कहा कि केंद्र ने राज्य से धान पर मौजूदा बोनस नीति की समीक्षा करने और इसे बंद करने पर विचार करने को कहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा है कि क्या वह इस संबंध में पत्र को सार्वजनिक करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, सीतारमण ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह आरोप कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को धान की खेती के लिए प्रोत्साहन न देने का निर्देश दिया है, तथ्यात्मक रूप से निराधार, राजनीतिक रूप से प्रेरित और तमिलनाडु के किसानों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर किया गया एक विकृत दावा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में 9 जनवरी, 2026 के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि सभी राज्य मुख्य सचिवों को- न केवल तमिलनाडु को - यह सुझाव दिया गया था कि राज्य की बोनस नीतियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाया जाए। इस पत्र में राज्यों से दालों, तिलहन और बाजरा को बढ़ावा देने के लिए अपनी बोनस

नोएडा हिंसा के बाद सख्त हुई योगी सरकार

मजदूर-उद्योग विवाद सुलझाने को बनी हाई लेवल कमेट

नोएडा। नोएडा में वेतन वृद्धि और न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर फैक्टरी कर्मियों द्वारा हिंसक प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एक बड़ा कदम उठाते हुए मजदूरों और उद्योगों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की दिशा में पहल की है।

उच्च स्तरीय समिति का गठन: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों में शांति और संतुलन बनाए रखना है।

इनको सौंपी गई समिति की कमान: गठित समिति की कमान औद्योगिक विकास आयुक्त को सौंपी गई है। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव (एमएसएमई) और प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन को भी इसमें सदस्य बनाया गया है। खास बात यह है कि समिति में श्रमिक संगठनों के पांच प्रतिनिधियों और उद्योग संगठनों के तीन प्रतिनिधियों को शामिल कर सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

ये होगा समिति का काम: सरकार का मानना है कि यह समिति संवाद और आपसी सहमति के जरिए विवादों को सुलझाएगी, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके और औद्योगिक माहौल स्थिर बना रहे।

नोएडा में कर्मचारियों की क्या हैं मांगे: नोएडा-ग्रेटर नोएडा की गारमेंट फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मचारी हरियाणा के नवीनतम मजदूरी दरों (15,220 रुपए-18,500+ रुपए) के अनुसार वेतन की मांग कर रहे हैं, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच वे अपना गुजारा कर सकें। वेतन में अनियमितता इसके आंदोलन का मुख्य कारण है, एक ही कार्य के लिए किसी कर्मचारी को 15 हजार तो किसी को 16 हजार और किसी को कुछ और वेतन दिया जाता है हरियाणा की तरह वेतन चाहते हैं नोएडा के प्रदर्शनकारीअकुशल श्रमिक=15,220 प्रति माहअर्ध-कुशल श्रमिक=16,780 प्रति माह, कुशल श्रमिक= 18,500 प्रति माह, श्रमिक= 19,425 प्रति माह।

इसके साथ ही उनका कहना है कि वेतन में अनियमितता को पूरी तरह समाप्त करेंकंपनियां सरकार के नियम अनुसार वेतन प्रदान करेंबिना उचित कारण के नौकरी से न निकाला जाएएक माह में चार अवकाश को सुनिश्चित किया जाएओवर टाइम का पैसा नियमों के अनुसार ही मिले ।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राजनीतिक लाभ के लिए आगे बढ़ाया

नईदिल्ली८ एजेंसी

संसद के विशेष सत्र से पहले महिला आरक्षण को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार पर इस बिल को राजनीतिक स्टंट के रूप में पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी मुद्दे पर 15 अप्रैल को होने वाली सर्वदलीय बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद आगे की रणनीति तय करेगी।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के अनुसार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मूल उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना है,इसका कांग्रेस पहले भी समर्थन कर चुकी है। हालांकि, उन्होंने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाकर कहा कि इस बिल को वर्तमान में राजनीतिक लाभ के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। यह विधेयक महिला आरक्षण को नई जनगणना और परिसीमन से जोड़ता है, जिससे इसके लागू होने में देरी की आशंका बनी हुई है।

मोदी सरकार की योजना के अनुसार, जनगणना में देरी को देखकर परिसीमन के लिए 2011 के आंकड़ों का उपयोग किया जा सकता है। प्रस्तावित संशोधनों के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 तक हो सकती है। इस प्रक्रिया के तहत एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, इस विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए अलग से कोई आरक्षण प्रावधान नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 16 अप्रैल से शुरू होने वाले तीन दिवसीय विशेष संसदीय सत्र में इस विधेयक और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इन दोनों को संवैधानिक संशोधन के रूप में पारित करना आवश्यक होगा, जिसके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति जरूरी है। इस बीच, नई दिल्ली में आयोजित 'नारी शक्ति वंदन सम्मेलन' में नरेंद्र मोदी ने इस पहल को नारी शक्ति को समर्पित ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर लोकतंत्र को और मजबूत करेगा।

मतदाता सूची से बाहर किए गए लोग नहीं कर पाएंगे मतदान

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में इसी महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान चरम पर है। इसी बीच अब विशेष गहण पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोमवार को साफ-साफ कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के खिलाफ अपील लंबित है, उन्हें आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। राज्य में चल रहे एसआईआर विवाद के बीच सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला चुनावी राजनीति में बड़ा मोड़ माना जा रहा है, जिससे पार्टियों के बीच टकराव और तेज हो सकता है।अदालत ने कहा कि जब तक संबंधित अपीलों पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक ऐसे व्यक्तियों को वोट देने की इजाजत देना कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी।

महिला आरक्षण नहीं, परिसीमन है असली मुद्दा : सोनिया गांधी

नईदिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा कि संसद के विशेष सत्र के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विधायी एजेंडा परिसीमन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है, जिसे उन्होंने अत्यंत खतरनाक और संविधान पर सीधा हमला बताया। द हिंदू में प्रकाशित एक लेख में गांधी ने कहा कि संसद के समक्ष मुख्य मुद्दा महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन प्रक्रिया के निहितार्थ हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकसभा की संख्या में कोई भी वृद्धि केवल गणितीय रूप से नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी न्यायसंगत होनी चाहिए।

सोनिया गांधी ने लेख में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विपक्षी दलों से उन विधेयकों का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं जिन्हें सरकार उस समय संसद के विशेष सत्र में पारित करना चाहती है जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर होगा। इस असाधारण तरीके की जल्दबाजी का केवल एक ही कारण हो सकता है, वह है राजनीतिक लाभ प्राप्त करना और विपक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में लाना। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री हमेशा की तरह सच्चाई से दूर हैं। उनका कहना है, संसद ने एक विशेष सत्र के दौरान सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को सर्वसम्मति से पारित किया था।

अधिनियम के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 334-ए जोड़ा गया, जिसने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य कर दिया। यह अगली जनगणना और जनगणना-आधारित परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद लागू होगा।'' उन्होंने कहा, ''विपक्ष ने यह शर्त नहीं मानी थी। दरअसल, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने 2024 के लोकसभा चुनाव से ही आरक्षण प्रावधान लागू करने की पुरजोर मांग की थी। सरकार इससे सहमत नहीं हुई। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि अब इस रुख से 'यू-टर्न' लेने में प्रधानमंत्री को 30 महीने क्यों लग गए? उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि सरकार ने विपक्ष की ओर से की गई सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग को ठुकरा दिया।

सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनावों के बीच संसद सत्र का आयोजन करना एक गुप्त रणनीति है जो निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री के एकाधिकार और उनके माई वे या हाइवे वाले दृष्टिकोण को दर्शाती है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने इस बात को याद दिलाया कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयक क्रमशः अप्रैल 1993 और जून 1993 में संसद द्वारा पारित किए गए तथा उन विधेयकों पर लगभग पांच साल तक चर्चा और विचार विमर्श हुआ था, जिसके बाद पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण कानून बना। उन्होंने कहा, यह दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक अनोखी उपलब्धि थी। उन्होंने दावा किया कि पिछली दशकीय जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन मोदी सरकार इसे टालती रही, जिसका एक परिणाम यह हुआ है कि 10 करोड़ से अधिक लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो गए हैं। उनका कहना है कि इस सत्र को बुलाने और परिसीमन कराने की जल्दबाजी के लिए सरकार के बहाने स्पष्ट रूप से खोखले हैं। सोनिया गांधी ने कहा, दरअसल, प्रधानमंत्री का असली इरादा अब जाति जनगणना को और विलंबित करना और पटरी से उतारना है।

उन्होंने कहा, विशेष सत्र 16 अप्रैल को शुरू होने वाला है। फिर भी, अब तक, सांसदों के साथ कोई आधिकारिक प्रस्ताव साझा नहीं किया गया है कि सरकार वास्तव में सत्र पर क्या विचार कराना चाहती है। ऐसा लग रहा है कि परिसीमन का कोई फॉर्मूला सुझाया जा रहा है। किसी भी परिसीमन से पहले पूर्व की भांति जनगणना प्रक्रिया होनी चाहिए। और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि लोकसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि से संबंधित कोई भी परिसीमन राजनीतिक रूप से होना चाहिए, न कि केवल अंकगणितीय रूप से।

खेल
प्रमुख समाचार

इम्पैक्ट प्लेयर नियम को हटाया जाना चाहिये : पोलार्ड

मुम्बई। आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर नियम शुरुआत से ही विवादों में रहा है। साल 2023 से लागू होने के बाद से ही कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि इससे ऑलराउंडरों को ही नुकसान हो रहा है। ऐसे में इस नियम को हटा दिया जाना चाहिये। वहीं अब मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी कोच कीरोन पोलार्ड ने भी कहा है कि इम्पैक्ट प्लेयर का विकल्प ऑलराउंडरों की भूमिका को सीमित कर रहा है। इससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। पोलार्ड लंबे समय से आईपीएल का हिस्सा हैं। वह 2010 से अलग-अलग भूमिकाओं में आईपीएल से जुड़े रहे हैं और टीम में ऑलराउडर के तौर पर भी शामिल रहे हैं। पोलार्ड ने कहा, मैं इस नियम को पसंद नहीं करता हूं पर इसे हटाना मेरे हाथ में नहीं है। इससे केवल ये हो रहा है कि इसने टी20 क्रिकेट में बड़े स्कोर बन रहे हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी इसके पड़ने वाले असर पर अभी तक मैंने धयान नहीं दिया है। आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर होने से केवल तब ही लाभ हो रहा है जब कोई टीम लीग गेम में कुछ विकेट गंवा देती है तो भी उसके पास अधिक रन बनाने का अवसर रहता है। उन्होंने जो लोग इस प्रकार के नियम बना रहे हैं उन्हें यह देखना चाहिये कि क्या यह वास्तव में खेल के लिए अच्छा है, टेलीविज़न के लिए अच्छा है, या सिर्फ़ लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इम्पैक्ट प्लेयर नियम के साथ, कुछ ऐसे कौशल सेट होत हैं जिनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रयोग नहीं हो रहा है। ऐसें में मेरा मानना है कि उनको इसकी समीक्षा करनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता हो ये इसी प्रकार जारी रहेगा। गौरतलब है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली सहित कई खिलाड़ियों ने अलग-अलग मौकों पर इस नियम की आलोचना की है। अक्षर पटेल ने सीजन शुरू होने से पहले कहा, मुझे यह नियम पसंद नहीं है, क्योंकि मैं एक ऑल-राउंडर हूं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

भारत पहुंचे ईरानी क्रूड के जहाज

नई दिल्ली। अमेरिका-इस्त्राइल-ईरान युद्ध के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में जारी जारी है और इसी दौरान लगभग सात साल के लंबे अंतराल के बाद ईरानी कच्चे तेल की खेप भारत पहुंची है। अमेरिका की ओर से दी गई प्रतिबंधों में अस्थायी छूट के चलते करीब 40 लाख (4 मिलियन) बैरल कच्चा तेल लेकर दो सुपरटैंकर भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पहुंचे हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब सप्ताहांत में अमेरिका-ईरान शांति वार्ता विफल हो गई है और वाशिंगटन ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी (ब्लॉकेड) का ऐलान किया है। शिप-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, नेशनल ईरानी टैंकर कंपनी द्वारा संचालित फेलिसिटी नामक एक बहुत बड़ा क्रूड कैरियर रविवार देर रात गुजरात के सिक्का तट पर लंगर डाल चुका है। इस जहाज में लगभग 20 लाख (2 मिलियन) बैरल कच्चा तेल है।

कच्चे तेल में उछाल, 100 डॉलर के पार पहुंचा भाव

नईदिल्ली। भू-राजनीतिक तनाव के बीच वैश्विक तेल बाजार में सोमवार को जोरदार उछाल देखने को मिला। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत विफल होने और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ते टकराव के कारण कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गईं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब 8त्न उछलकर 102.80 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी कच्चा तेल डब्ल्यूटीआई भी 8% से ज्यादा बढ़कर 104.88 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करने लगा। इससे पहले शुक्रवार को दोनों बेंचमार्क में गिरावट देखी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य में नाकेबंदी की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रोजाना लाखों बैरल तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

ईवी को बढ़ावा, हाइब्रिड पर कटौती

नईदिल्ली। सरकार ने 2027 के लिए कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मानकों का मसौदा नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें अनुपालन मापने के तरीके में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। नए ढांचे के तहत अनुपालन का आकलन अब सालाना आधार पर नहीं, बल्कि तीन साल के ब्लॉक जैसे वित्त वर्ष 2028-30 और 2030-32 में किया जाएगा। इससे वाहन निर्माताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत चरणबद्ध तरीके से करने के लिए अधिक समय और लचीलापन मिलेगा। प्रस्तावित नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होने की उम्मीद है। मजबूत हाइब्रिड वाहनों के लिए प्रोत्साहन कम कर दिया गया है, जहां सुपर-क्रेडिट को 2.0 गुना से घटाकर 1.6 गुना कर दिया गया है। छोटे वाहनों के लिए पहले प्रस्तावित 3 ग्राम सीओ2 प्रति किलोमीटर की छूट भी हटा दी गई है। साथ ही, मसौदे में 'डेरोगेशन टेक्नोलॉजी' की शुरुआत की गई है।

प्रमुख त्योहारों के कारण आज बैंक रहेंगे बंद

नईदिल्ली। अगर आप बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। मंगलवार, 14 अप्रैल को देश के अधिकांश राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, इसलिए घर से निकलने से पहले छुट्टियों की जानकारी जरूर चेक कर लें। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कैलेंडर के अनुसार, 14 अप्रैल को कई प्रमुख त्योहारों और खास अवसरों के चलते बैंक अवकाश रहेगा। इस दिन डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती, बैसाखी, तमिल नववर्ष (पुथांडु), बोहाग बिहु, महाबिषुब संक्रांति, बुइसु महोत्सव और चेइराओबा जैसे पर्व मनाए जाएंगे, जिसके कारण ज्यादातर राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। पंजाब में बैसाखी फसल कटाई का प्रमुख त्योहार है, जबकि असम में बोहाग बिहु नए साल की शुरुआत का प्रतीक है।

अमेरिका-ईरान युद्ध ने दुनिया भर में ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों का लाया सामने

सुनीता नारायण

अमेरिका और इजरायल ने ईरान के विरुद्ध जो विनाशकारी युद्ध छेड़ा उसने दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति में उथलपुथल पैदा कर दी है। अमीर और गरीब दोनों तरह के मुल्क अपने नागरिकों को चेतावनी दे रहे हैं कि मुश्किल समय आने वाला है। ऐसा संकट जो शायद इस पीढ़ी ने तो नहीं झेला यानी ऊर्जा (ईंधन) की भारी कमी और राशनिंग। यहां तक कि कारों और विमानों के भी ईंधन से रहित हो जाने का खतरा सामने है। सवाल यह है कि भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र का मानचित्र कैसा होगा?

जिस समय मैं यह सवाल कर रही हूं हजारों जान जा चुकी हैं और हम अपनी स्क्रीन्स पर निरर्थक विनाश को साफ देख सकते हैं। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें इस ऊर्जा व्यवधान के कारण दुनिया में हो रही दिक्कतों को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई देशों में खाना पकाने के ईंधन खासतौर पर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कमी हो रही है। आम परिवार किसी कीमत पर गैस पाने के लिए अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च कर दे रहे हैं। गैस एजेंसियों-पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें फिर से आम हो रही हैं। इससे लागत बढ़ रही है जिसे लोग मुश्किल से वहन कर पा रहे हैं।

अधिकांश देशों में, खासकर हमारे क्षेत्र में ईंधन आयात व्यापार घाटे पर सबसे बड़ा बोझ है और इस परिदृश्य में बढ़ती तेल कीमतें अर्थव्यवस्था को पंगु बना देने की हद तक असर डाल सकती हैं। इसके अलावा, वैश्विक उर्वरक आपूर्ति में आसन्न कमी से किसानों को कड़ी चोट पहुंचने की उम्मीद है। ये वे किसान हैं जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम और विकृत वैश्विक खाद्य कीमतों से जूझ रहे हैं।

यहां यह सवाल आता है कि ऊर्जा क्षेत्र को लगे इस झटके का क्या असर होगा? युद्ध की शुरुआत के पहले भी दुनिया ऊर्जा में बदलाव के दौर से गुजर रही थी। चरणबद्ध तरीके से कोयले का स्थान नवीकरणीय ऊर्जा ले रही थी। वाहनों में बिजली, पेट्रोल और डीजल की जगह ले रही थी। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की मार्च 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के आखिर तक नवीकरणीय ऊर्जा दुनिया की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता के 50 फीसदी के करीब है। साल के दौरान जो नया बिजली उत्पादन शामिल हुआ, उसका 85 फीसदी नवीकरणीय ऊर्जा से आया। मुख्य रूप से सौर और पवन ऊर्जा से।

दिलचस्प बात यह है कि यह ऊर्जा परिवर्तन केवल चीन या यूरोप में नहीं हो रहा था जहां इसके होने की उम्मीद थी। हाल ही में थिंक टैंक एम्बर द्वारा 74 सबसे जलवायु-संवेदनशील देशों के गठबंधन के साथ मिलकर जारी की गई एक रिपोर्ट में पाया गया कि ये देश इलेक्ट्रो-टेक को तेजी से अपना रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि यह तेज, सस्ता और अधिक विश्वसनीय है।

ये निम्न और मध्यम आय वाले देश ईंधन आयातक हैं और उनके लिए ऊर्जा संकट वास्तविक है यानी 70 करोड़ से अधिक लोगों के पास अभी भी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए विश्वसनीय ऊर्जा नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि वे अभी तक ग्रिड से जुड़े नहीं हैं और इसलिए वे वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली को तेजी से और बड़े पैमाने पर अपना सकते हैं। सौर पैनलों, बैटरियों और इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत अब किफायती हो गई है और चीन से आयात उनके लिए उपयोगी है। ये देश जीवाश्म ईंधन को दरकिनार कर सकते हैं और नवीकरणीय ऊर्जा को तीव्र गति से अपना सकते हैं।

रिपोर्ट में पाया गया है कि 'नामीबिया और टोगो सौर उत्पादन में अग्रणी हैं, जॉर्डन और किर्गिजिस्तान बैटरी बिक्री में और नेपाल और श्रीलंका ईवी अपनाने में।' नेपाल और श्रीलंका में लगभग 70 फीसदी नए वाहन इलेक्ट्रिक थे।

वर्तमान व्यवधान ने ऊर्जा आयात की लागत ?बढ़ा दी है और देशों को ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता का एहसास कराया है। पहले

बस्तर में स्वास्थ्य क्रांति की नई शुरुआत

■ हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण और सुलभ चिकित्सा पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताः मुख्यमंत्री

रायपुर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः की भारतीय जीवनदृष्टि को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सुकमा जिला चिकित्सालय में 'अटल आरोग्य लैब' का राज्यस्तरीय शुभारंभ किया। यह पहल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई क्रांति का आधार बनेगी, जो विशेष रूप से दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के नागरिकों को आधुनिक एवं सुलभ जांच सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि राज्य शासन का स्पष्ट संकल्प है कि प्रदेश के हर नागरिक तक उत्कृष्ट, किफायती और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएं। उन्होंने कहा कि अटल आरोग्य लैब के माध्यम से अब प्रदेश के 1046 स्वास्थ्य संस्थानों - जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक -मुफ्त जांच की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे लाखों नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा। इस अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली के माध्यम से मरीजों को 133 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। जांच रिपोर्ट एसएमएस और व्हाट्सऐप के माध्यम से सीधे मरीजों तक पहुंचेगी, जिससे उन्हें बार-बार अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं होगी और उपचार प्रक्रिया में तेजी आएगी। यह व्यवस्था न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुलभ भी बनाएगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश की डायग्नोस्टिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। इससे रक्त जांच सहित विभिन्न रोगों की पहचान शीघ्र और सटीक रूप से संभव होगी, जिससे समय पर उपचार शुरू कर मरीजों के स्वास्थ्य लाभ की दर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष रूप से बस्तर जैसे दूरस्थ अंचलों में ऐसी आधुनिक सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की प्राथमिकता है, ताकि यहां के नागरिकों को बेहतर इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। अटल आरोग्य लैब इस दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करेगी।

उल्लेखनीय है कि जिला चिकित्सालय सुकमा में पहले से ही ब्लड बैंक, सोनोग्राफी, एक्स-रे, ईसीजी, आपातकालीन सेवाएं, सीजेरियन प्रसव, एनआरसी एवं डायलिसिस जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब अटल आरोग्य लैब के जुड़ने से यहां की स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक हो जाएंगी।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, बस्तर सांसद महेश कश्यप, महिला आयोग सदस्य सुदीपिका सोरी, कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी. सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

युवा शक्ति ही विकसित भारत की वास्तविक शक्ति हैः संस्कृति मंत्री

रायपुर। नया रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी में 'माय भारत बजट क्रेस्ट 2026' के भव्य शुभारंभ के अवसर पर छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि युवा शक्ति ही विकसित भारत की वास्तविक शक्ति है और यह आयोजन युवाओं को आर्थिक नीतियों और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की दिशा में एक सशक्त मंच प्रदान करता है।यह कार्यक्रम भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत संचालित 'माय भारत' पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय बजट 2026 के प्रति युवाओं और आमजन की समझ को सुदृढ़ करना है, ताकि बजटीय प्रावधानों को अधिक सुलभ, प्रासंगिक और नागरिक-केंद्रित बनाया जा सके। कार्यक्रम में देशभर से लगभग 30 हजार युवाओं में से चयनित 471 प्रतिभागियों की उपस्थिति इस आयोजन की व्यापकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाती है। मुख्य अतिथि अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि बजट केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि देश के विकास का रोडमैप होता है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

प्रदेश में कानून नहीं, जंगलराज चल रहा : दीपक बैज

रायपुर। पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार में जंगलराज चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अपराध का डर, भय खत्म हो गया है। भैरमगढ़ की घटना जिसमें एक नबालिक के साथ सामूहिक दुष्कर्म चिंता का विषय है। इस तरह की घटनाये पूरी प्रदेश में घट रही है। तीन दिन पहले दुर्ग में पांच साल की बच्ची से रेप, अंबिकापुर अधेड़ महिला के साथ रेप और रायपुर में झाड़ी में छुपकर रात काटना पड़ रहा है। भाजपा के कांकेर जिला उपाध्यक्ष पर दुष्कर्म और यौन शोषण का आरोप लगे लगभग 1 महिने हो रहे है, अब तक एफआईआर नहीं लिखी गई, उल्टे पीड़िता पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। प्रदेश रेप, चाकूबाजी, चोरी, डकैती चरम सीमा पर है। ऐसा लग रहा छत्तीसगढ़ में सरकार कही भी नही है और छत्तीसगढ़ भगवान भरोसे चल रहा है। राजधानी में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है। सरकार और पुलिस आपराधिक घटनाओं को रोक पाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। डीएसपी की बेटी, आदिवासी संस्कृति पर कंटेंट बनाने वाली, एक आदिवासी छात्रा निवेदिता मांडवी को सोशल मीडिया पर गैंगरेप की धमकी मिल रही हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में गुंडे, मवालियों के हौसले इतने बुलंद हैं।

राजधानी सहित प्रदेश में नकली पनीर सरकारी लापरवाहीः शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों सहित राजधानी में लगातार बन रही नकली पनीर बेहद चिंता का विषय है। यह सरकार के खाद्य एवं औषधि विभाग की लापरवाही है कि लगातार प्रदेश में नकली पनीर खुलेआम बन रही है और बिक रही है। जानवरो की चर्बी और तेल तथा सोडे से पनीर बनाया जा रहा, सरकार क्या रही है? कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि नकली पनीर के निर्माण और बिक्री पर रोकथाम के लिये सरकार विशेष दल का गठन करें और प्रदेश के किसी भी कोने में बन रही नकली खाद्य सामाग्री पर कड़ाई से रोक लगाई जाये। प कहा कि भाजपा के कुशासन में आम जनता की सेहत भगवान भरोसे है। खाद्य और औषधि विभाग की कार्यवाही केवल नोटिस और चालान तक ही सीमित है। प्रदेश के 33 जिलों के लिये केवल 9 मोबाइल यूनिट है और ये भी विगत 2 वर्षो से बंद है। इस सरकार के पास इन्हें संचालित करने फंड नहीं है। नकली दूध, खोवा, पनीर एवं अन्य खाद्य पदार्थो का धंधा राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद बढ़ गया है। इस बात की संभावना से इंकार नही किया जा सकता कि सत्ता रूढ़ दल के संरक्षण के बिना इस प्रकार की गतिविधि संभव नहीं है।

स्कूल में शिक्षक नहीं, स्वीपर करा रहे है पढ़ाईः ठाकुर

रायपुर। सरसींवा वन क्षेत्र के शिक्षक विहीन प्राथमिक शाला रनकोट में स्वीपर पर स्कूल की पूरी जिम्मेदरीं को भाजपा सरकार की शिक्षा विरोधी करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पर विधानसभा में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी थी कि प्रदेश में कोई स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है फिर सरसींवा के रनकोट स्कूल में स्वीपर कैसे पढ़ाई करा रहे है? परीक्षा से लेकर स्कूल की सारी जिम्मेदारी स्वीपर कैसे निर्वहन कर रहा है? स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? ये नवनिहाल बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है? शिक्षक नहीं होने की जानकारी डीओ, बीओ को है ऐसे में साल भर तक शिक्षक की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? गर्मिन बार अधिकारियों को जानकारी दे रहे थे शिक्षक की मांग कर रहे थे फिर जिम्मेदारों ने मांग को अनसुना क्यों किया? क्या मंत्री को भी गलत जानकारी दी गई? इसकी जाँच होनी चाहिये जिम्मेदारों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये?प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा भाजपा सरकार में शिक्षा व्यवस्था बेहद खराब हो गई है, स्कूलों में 60 हजार से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त है, कई स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे है।

कमीशनखोरी का अभिनव प्रयास स्वास्थ्य विभाग काः वर्मा

रायपुर। अस्पतालों की पैथोलॉजी ठेके पर दिये जाने पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का पीपीपी मॉडल है, कंडोम बनाने वाली कंपनी को टेस्ट का ठेका दे दिया। यह कंपनी है तो सरकारी, लेकिन ठेकेदार से काम करायेगी। लैब की जगह, कर्मचारी लगने वाली मशीनें सभी सरकार मुफ्त में देगी और ठेका कंपनी जांच करेगी और जांच में लगने वाली फीस का भुगतान भी सरकार करेगी। यह ठेका स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार का अभिनव पहल है। स्वास्थ्य विभाग लोगो के इलाज की दिशा तय करने नही भ्रष्टाचार करने की रोज नये अवसर खोजता है। बिना किसी टेंडर के एच.एल.एन को ठेका दिया तथा एच.एल.एन ने महाराष्ट्र की कंपनी को ठेका दे दिया। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि जब मशीने सरकारी है, लैब के लिये स्थान भी सरकार देगी तथा टेक्नीशियन भी सरकार ही देगी तथा जांच की फीस भी सरकारी है तो ठेका कंपनी को केवल बिल काटने के लिये रखा गया है। राज्य में जब से भाजपा की सरकार बनी है, स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग की पहचान बन गयी है।

ओबीसी के लिए अलग कॉलम देने आप ने सौंपा ज्ञापन

रायपुर। आगामी डिजिटल जनगणना (16 अप्रैल से 30 अप्रैल) और 1 मई से 30 मई भौतिक सत्यापन के लिए प्रथम चरण में निर्धारित 33 बिंदुओं में ओबीसी वर्ग के लिए अलग से कॉलम नहीं होने पर ओबीसी वर्ग की उपेक्षा किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा आज 13 अप्रैल 2026 को रायपुर के कलेक्टर के जरिये महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि सरकार ओबीसी वर्ग के लिए दोहरा मापदंड अपना रही है।मंडल आयोग (1980) के अनुसार देश में ओबीसी की आबादी 32% बताई गयी थी और सर्वेक्षण (आईसीई 360, 2021) के अनुसार भारत की अनुमानित 141 करोड़ की आबादी में, लगभग 44%-48% आबादी यानि की 62-68 करोड़ लोग ओबीसी समूह से आतें हैं। देश की आधी आबादी की अनदेखी समझ से परे है? पिछड़े समाज के विकास की बात करने वाली केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की साय सरकार आज इस मामले में असहाय क्यों नज़र आ रही है, क्या पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है सरकार? राजपत्र के बिंदु क्रमांक 12 में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए स्पष्ट कॉलम दिया गया है, लेकिन ओबीसी वर्ग की गणना के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

छत्तीसगढ़ शासन
सत्यमेव जयते

मैं किसी समुदाय की प्रगति का आकलन इस आधार पर करता हूं कि महिलाओं ने कितनी प्रगति हासिल की है।
— बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर

संविधान निर्माता, भारत रत्न
बाबा साहेब
डॉ. भीमराव अंबेडकर जी
को उनकी जयंती पर कोटिशः नमन

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

संवाद-47481/161

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.